साप्ताहिक
शांति मिशन
नई दिल्ली

वर्ष-28 अंक- 44 31 अक्तूबर -06 नवंबर 2021 पृष्ठ 12

अन्दर पढ़िए

चुनौती समान अवसर की
पृष्ठ-6

जर्मनी के नतीजों का संदेश
पृष्ठ-7

लोकसभा चुनाव-2024 के लिए विपक्ष का गठबंधन

क्या ममता बनर्जी मोदी का मुक़ाबला कर सकेंगी?

भवानीपुर से रिकॉर्ड मतों से सफलता प्राप्त करने के बाद ममता बनर्जी अत्याधित उत्साहिक नज़र आ रही हैं और अब उनकी नज़र 2024 के संसदीय चुनावों पर है।

भवानीपुर उप-चुनाव से पहले 26 सितंबर को एक नुक्कड़ बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया :''*भबानीपुर थेके आर एकटा खेला शूरू हॅबे. ई खेला शेष हॅबे भारतबर्ष जॉय करे*'' (भवानीपुर में एक नया खेल शुरू हुआ है, जिसकी परिणति भारत को जीतने में होगी)। ''तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख ने हाल फिलहाल यह संदेश देना शुरू किया है कि उनकी पार्टी बंगाल विधान सभा चुनाव में जीत के बाद हासिल अपनी मौजूदा स्थिति से संतुष्ट होकर नहीं बैठ जाएगी और अब इसकी निगाहें दिल्ली पर टिक गई हैं। उसी सभा में टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने इसे थोड़ा खुलकर कहा, ''याद रखिए, आप सिर्फ दीदी के लिए वोट नहीं कर रहे, आप दिल्ली में बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं।''

यहां एक साथ दो अभियान चल रहे हैं : पहला 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा से मुक़ाबला करने के लिए एक लचीला विपक्षी गठबंधन बनाना, दूसरा ममता बनर्जी को उस समूह के नेता के रूप में पेश करना है। पिछले एक या दो माह में टीएमसी के दिग्गजों ने इस बात पर चर्चा को बढ़ावा दिया है कि नेतृत्व करने के लिए सबसे अच्छा कौन है। इस तथ्य पर प्रकाश डालते हुए कि भाजपा के ख़िलाफ़ टीएमसी की लड़ाई सबसे विश्वसनीय थी - विशेष रूप से, चुनावों में मोदी/शाह के नेतृतव वाले चौतरफा हमले झेल पाने के कारण - अभिषेक जैसे टीएमसी नेताओं ने संभावित दावेदार पर ममता के दावे पर बात करना शुरू कर दिया है। उदाहरण के लिए, वे कांग्रेस नेताओं के बारे में कहते हैं कि उन्होंने या तो हार मान ली है या छिप गए हैं। उनकी नई मुखरता कमज़ोर विपक्षी एकता को आसानी से नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन टीएमसी का मानना है कि ममता के लिए शीर्ष स्थान के लिए दांव खेलने का समय आ गया है।

कई मामलों में, भाजपा इस समय बैकफुट पर है-ईंधन, पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं, महंगाई बढ़ रही है और पिछले डेढ़ वर्ष में महामारी ने गहरा आर्थिक संकट पैदा किया है। कुछ लोगों का तर्क है कि इससे निश्चित तौर पर सत्ता विरोधी लहर उठेगी और ममता को खुद को भाजपा के विकल्प के तौर पर पेश करने का उतना ही अच्छा मौक़ा मिलेगा, राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रे के अनुसार, 2014 के लोकसभा चुनाव में भी ऐसी ही स्थिति मौजूद थी, जब घोटाले से ग्रस्त यूपीए-2 सत्ता विरोधी लहर से जूझ रहा था, जो अंततः उसकी हार का कारण बना। उस समय, भाजपा ने संकट का फायदा उठाते हुए नरेन्द्र मोदी को एक ऐसे नेता के रूप मे पेश किया था जो 'अच्छे दिन' की शुरुआत कर सकता था, उन्हें तीन बार के मुख्यमंत्री के रूप में सफल बताते हुए और भारत की आर्थिक परेशानी के लिए विकास के गुजरात मॉडल को रामबाण बताया। टीएमसी भी उसी तर्ज़ पर चल रही है - इस बार उसका टैग लाइन ''भारत निजेर मेयेकेइ चाइ'' (भारत को अपनी ही बेटी चाहिए)।

हालांकि ममता बनर्जी ने अब तक खुले तौर पर संभावित विपक्षी गठबंधन के नेतृत्व का दावा करने से परहेज़ किया है, लेकिन उन्होंने पश्चिमी बंगाल के रास्ता दिखाने के बारे में अपने बयानों से संभावना की ओर इशारा किया है। कड़े मुक़ाबले में लड़े गए विधानसभा चुनाव में अपनी बड़ी जीत के तुरंत बाद, उन्होंने घोषणा की, ''बंगाल ने भारत को बचा लिया है'' टीएमसी के राज्यसभा सांसद और प्रसार भारत के पूर्व सीईओ जवाहर सरकार कहते हैं कि इस चुनावी जीत ने उन्हें बिलाशक राष्ट्रीय क़द का बना दिया है। वे कहते हैं 'प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिमी बंगाल का 18 बार दौरा किया, केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 21 बार। इन्होंने चुनाव को जीवन मरण का प्रश्न बना दिया था। ममता इस असाधारण जीत को विपक्ष के एकजुट करने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। जो (भाजपा के इशारे पर केन्द्रीय जांच एजेंसियों की) छापेमारी से हिला हुआ नज़र आ रहा है, पर वे डरने वाला नहीं है। इस संदर्भ में, ममता का 'तृणमूल ही काफी है' नारा भाजपा के ख़िलाफ़ अभियान शुरू करने में अन्य विपक्षी दलों की भी चुनौती जैसी लग रही है।

टीएमसी की आक्रामक बयानबाज़ी में कुछ ग़लत नहीं लगता यह कहना है जवाहर सरकार का, जो आमतौर पर कांग्रेस पर निशाना साधती प्रतीत होती है। वे कहते हैं ''ममता (अपना यह विश्वास) नहीं छिपाती हैं कि कांग्रेस को और अधिक ऊर्जावान होने की ज़रूरत है।''' रे भी ऐसी ही बात कहते हैं कि ममता विपक्ष को तेज़ी से एकजुट करने की कोशिश कर रही हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि देरी का फायदा भाजपा को ही मिलेगा। वे कहते हैं 'हम बैठकर कांग्रेस के अधिक सक्रिय होने का इंतज़ार नहीं कर सकते। बड़ा सवाल यह नहीं है कि नेतृत्व कौन कर रहा है, बड़ा प्रश्न भाजपा से लड़ने के लिए एक बैनर के तहत एक साथ आने का है।''

यह भी सच है कि कई नेताओं का कांग्रेस नेतृत्व से मोहभंग हो गया है, जिससे ममता के लिए शीर्ष स्थान का दावा करने के लिए मैदान खुला है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और गोवा के दो बार के पूर्व मुख्यमंत्री लुइजिन्हो फलीरो टीएमसी में शामिल होने वालों में से एक हैं। बीती 29 सितंबर को टीएमसी प्रमुख से राज्य मुख्यालय नवन्ना में मुलाक़ात के बाद उन्होंने कहा, ''ममता ने पहले ही साबित कर दिया है कि वे भाजपा को हरा सकती है। अब वक़्त आ गया है कि हम एक नए नेता को प्रोजेक्ट करें जो देश को एक नई दिशा दे सकता हो।''

पश्चिम बंगाल की जीत का मनोवैज्ञानिक महत्व बहुत बड़ा है। इस तथ्य के बावजूद कि टीएमसी की राष्ट्रीय उपस्थिति नगण्य है और देश के अन्य हिस्सों में उसका कोई विधायक नहीं है, कई सियासी पर्यवेक्षक पहले से ही टीएमसी को एक क्षेत्रीय दल से कहीं अधिक देखते हैं। हालिया संघर्ष ने पार्टी को नई प्रतिष्ठा दिलाई है। उदाहरण के लिए, केवल फलीरो और गोवा में उसके 10 सहयोगियों को अपने साथ लाने की कामयाबी ने पार्टी को राज्य में एक खिलाड़ी बना दिया है।

उत्तर प्रदेश में वह समाजवादी पार्टी के साथ गठजोड़ की कोशिश कर रही है। बंगाल में भाजपा के पूर्व अध्यक्ष बाबुल सुप्रिया और कांग्रेस की सुष्मिता देव ने भी दल बदल लिया है। इस तरह के घटनाक्रम ममता को राष्ट्रीय नेता के रूप में समर्थन देने का संकेत देते हैं, वैसे अभी इसके शुरुआती दिन हैं। आने वाले दिनों में, टीएमसी अधिक से अधिक वरिष्ठ नेताओं को शामिल करने की कोशिश करेगी। इससे पहले कि वह अगले दो सालों में अन्य राज्यों के विधान सभा चुनावों में मुट्ठीभर सीटें जीतने की कोशिश करे वह अन्य राज्यों में सियासी पदचिह्न बनाना चाहेगी - विशेषकर छोटे राज्य, जहां यह आसान हो सकता है। देव और फलीरो के अलावा,

उत्तर प्रदेश में वह समाजवादी पार्टी के साथ गठजोड़ की कोशिश कर रही है। बंगाल में भाजपा के पूर्व अध्यक्ष बाबुल सुप्रिया और कांग्रेस की सुष्मिता देव ने भी दल बदल लिया है। इस तरह के घटनाक्रम ममता को राष्ट्रीय नेता के रूप में समर्थन देने का संकेत देते हैं, वैसे अभी इसके शुरुआती दिन हैं। आने वाले दिनों में, टीएमसी अधिक से अधिक वरिष्ठ नेताओं को शामिल करने की कोशिश करेगी। इससे पहले कि वह अगले दो सालों में अन्य राज्यों के विधान सभा चुनावों में मुट्ठीभर सीटें जीतने की कोशिश करे वह अन्य राज्यों में सियासी पदचिह्न बनाना चाहेगी - विशेषकर छोटे राज्य, जहां यह आसान हो सकता है। देव और फलीरो के अलावा, जिनके पास अपने खास समर्थक हैं, टीएमसी त्रिपुरा के प्रद्योत देबबर्मा, राज्य के सबसे बड़े स्थानीय समूह टीआइपी आरए (द इंडिजीनस पीपुल्स रीजनल अलायंस) मोथा के मुखिया - जैसे नेताओं को भी शामिल करना चाह रही है।

बाक़ी पेज 11 पर

अगले दस सालों में और बहुआयामी होंगे भारत-सऊदी अरब के रिश्ते

सऊद बिन मुहम्मद अली सती

सवाल:- सऊदी अरब के विज़न 2030 की क्या प्रगति है?

जवाब:- आपको मालूम होगा कि सऊदी अरब किंगडम ने वर्ष 2016 में विजन-2030 को जारी किया था। हमने 500 सुधारों को लागू करने का फैसला किया था और इसमें से 45 प्रतिशत को पूरा कर लिया गया है। हमने विदेशी उद्योगपतियों को सौ प्रतिशत सुरक्षा देने का फैसला किया है। देश में 5500 लाइसेंसिंग नियमों में सुधार करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें से 60 प्रतिशत में सुधार हो चुका है या उन्हें ख़त्म किया जा रहा है। इसका असर यह हुआ है कि पिछले पांच सालों में ग़ैर तेल कारोबार से होने वाले रिजर्व में 222 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वहां के वर्क फोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी 19.4 प्रतिशत से बढ़कर 33.3 प्रतिशत हो चुकी है। वर्ष 2021 की पहली तिमाही में 478 विदेशी निवेशकों को लाइसेंस दिया गया है। सऊदी अरब में कारोबार करने को आसान बनाने का भारतीय कंपनियों को भी फायदा होगा।

सवाल:- इस संदर्भ में भारत के साथ रिश्तों की क्या दिशा होने जा रही है?

जवाब:- दोनों देशों के बीच रणनीतिक रिश्ते हैं जैसे सऊदी अरब किंगडम और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की ओर से बहुआयामी बनाने का फैसला किया गया हैं। पिछले दिनों सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फेजल बिन फरहान अल सऊद ने भारत की यात्रा की थी और विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ उनकी बातचीत में कारोबारी, ऊर्जा, डिफेंस, सिक्यूरिटी, संस्कृति, स्वास्थ्य और एक दूसरे के नागरिकों को सुविधा देने से जुड़े विषयों पर हाल में प्रगति की समीक्षा की है। कोरोना की स्थिति थोड़ी और सुधरने के बाद दोनों देशों के बीच उच्चस्तरीय दौरे भी होंगे। अगले 10 सालों में भारत और सऊदी अरब के द्विपक्षीय रिश्ते कई मायनों में बहुआयामी होंगे।

सवाल:- ऊर्जा क्षेत्र में हम आपसी रिश्तों को किस ओर ले जा रहे हैं क्योंकि अभी तक तो यह कच्चे तेल की ख़रीद तक ही सीमित था?

जवाब:- ऊर्जा क्षेत्र में हमारे द्विपक्षीय रिश्ते काफी अच्छे हैं। सऊदी अरब ने ग़ैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया है और हमें लगता है कि भारत के साथ हम काफी अच्छे संबंध बना सकते हैं। जिस तरह कच्चे तेल की खरीद में हमारे रिश्ते रहे हैं, वैसे ही हम रिन्यूबल एनर्जी में भी बना सकते हैं। भारत के साथ इन नए ऊर्जा क्षेत्रों में रिश्ते बनने भी लगे हैं। सऊदी अरब बड़े पैमाने पर सोलर एनर्जी और हाइड्रोजन एनर्जी को बढ़ावा दे रहा है ताकि वर्ष 2030 तक हमारी अर्थव्यवस्था में पारंपरिक एवं ग़ैर पारंपरिक ऊर्जा का अच्छा मिश्रण हो। भारत में भी ग्रीन एनर्जी को लेकर काफी काम हो रहा है और हमारे बीच रणनीतिक रिश्तों को यहां बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं।

सवाल:- कोरोना महामारी से दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों पर किस तरह का असर हुआ है?

जवाब:- कोरोना महामारी ने हमारे

बाक़ी पेज 11 पर

बलूचों के हमलों से डरे चीन-पाकिस्तान

ग्वादर नहीं अब कराची को बनाएंगे सीपीईसी का हब

पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में बलूच विद्रोहियों के लगातार हमलों से घबराए चीन और पाकिस्तान ने ग्वादर बंदरगाह को चाइना-पाकिस्तान आर्थिक कॉरोडोर का केन्द्र बनाने की योजना को त्याग दिया है। चीन की सीपीईसी परियोजना उसकी बेल्ट एंड रोड परियोजना का हिस्सा है। चीन और पाकिस्तान के बीच अब कराची बंदरगाह को विकसित करने की योजना पर हाल ही में हस्ताक्षर हुआ है। कराची शहर सिंध प्रांत की राजधानी और पाकिस्तान के आर्थिक गतिविधियों का केन्द्र है। जापानी अख़बार निक्केई के मुताबिक पाकिस्तान की ओर से जारी सूचना के मुताबिक चीन करीब साढ़े तीन अरब डॉलर इस परियोजना पर ख़र्च करेगा। चीन के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने इस ख़बर की पुष्टि भी की है। इस परियोजना के तहत कराची पोर्ट का विस्तार, मछली पकड़ने के लिए एक अन्य बंदरगाह का निर्माण और 640 हेक्टेयर के इलाक़े में व्यापारिक जोन की स्थापना करना शामिल हे। इसमें एक पुल भी बनाया जाएगा जो कराची बंदरगाह को मनोरा द्वीप समूह से जोड़ेगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने कराची को सीपीईसी में शामिल किए जाने को 'गेमचेंजर' करार दिया है। इमरान ने टवीट करके कहा, 'इस परियोजना से हमारे मछली पकड़ने वाले लोगों के लिए समुद्री इलाक़ा साफ करने में मदद मिलेगी। कम आय वाले लोगों के लिए 20 हजार घर बनाए जाएंगे। साथ ही निवेशकों के लिए अवसर मिलेंगे। इससे कराची विकसित बंदरगाह शहरों में शामिल हो जाएगा।' दरअसल चीन के लिए ग्वादर बंदरगाह बड़ा संकट बन गया था जो बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। चीनी नागरिकों और उसके निवेश पर लगातार बलूच विद्रोही हमले कर रहे थे। ❑❑

एम्स समेत 8 बड़े अस्पतालों में बनाए जाएंगे मिनी दमकल केन्द्र

राजधानी के अस्पतालों में बढ़ती आग की घटनाओं को लेकर दिल्ली फायर सर्विस चिंतित है। अस्पताल में आग लगने की सूरत में तुरंत ही वहां राहत और बचाव कार्य शुरू हो सके इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दीं हैं। एम्स समेत दिल्ली के आठ अन्य बड़े अस्पतालों में दमकल केन्द्र बनाने की योजना पर काम चल रहा है। अधिकारियों का कहना है कि 500 या उससे अधिक बिस्तरों वाले अस्पतालों में इसकी शुरुआत की जा रही है। अस्पताल प्रशासन इसके लिए दमकल की गाड़ी खड़ी करने की जगह के अलावा पानी का इंतज़ाम करके देगा। फिलहाल, इसकी शुरुआत एम्स से होने जा रही है। इससे तुरंत ही बचाव कार्य शुरू किया जा सकेगा।

दमकल विभाग के अधिकारी ने बताया कि पिछले दिनों एम्स और सफदरजंग में आग लगने की कई घटनाएं हुईं। इसके बाद विचार किया गया कि आग लगने की सूरत में कैसे जल्द से जल्द बचाव हो सके। हालांकि, दिल्ली के ज़्यादातर बड़े अस्पतालों के दो से तीन किलोमीटर के दायरे में दमकल केन्द्र मौजूद हैं, लेकिन कॉल रिस्पांस समय को ओर कम करने के लिए इस पर विचार किया गया। तय हुआ कि यदि अस्पताल परिसर में ही एक गाड़ी वाला छोटा दमकल केन्द्र बना दिया जाए तो इससे तुरंत बचाव किया जा सकता है। इसको लेकर अस्पताल प्रशासन से बातचीत की की गई। सबसे पहले एम्स प्रशासन ने इसकी मंज़ूरी दी। एम्स ने दमकल विभाग को फायर की एक गाड़ी खड़ी करने की जगह देने का वादा किया। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही एम्स में इसकी शुरूआत कर दी जाएगी। बाकी आठ अस्पतालों में भी इसकी तैयारी की जा रही है।

इन अस्पतालों में चल रही तैयारी

- सत्यवादी राजा हरीशचंद्र, नरेला
- महर्षि बाल्मीकि, पूठ खुर्द
- दीनदयाल उपाध्याय, हरी नगर
- बाड़ा हिन्दूराव, बाड़ा हिंदूराव
- आईएलबीएस, वसंत कुंज
- बाबा साहब आंबेडकर, रोहिणी
- आरएमएल, नई दिल्ली
- एलआरएस टीबी, अरबिंदो मार्ग

14 जनवरी, सफदरजंग अस्पताल में चौथी मंज़िलपर आग लगी। कोई हताहत नहीं, लेकिन मरीज़ों को दूसरी जगह करना पड़ा शिफ्ट।

31 मार्च, सफदरजंग अस्पताल की पहली मंज़िल स्थित, आईसीयू में लगी आग। 50 मरीज़ों को दूसरी जगह किया गया शिफ्ट।

05 मई, विकासपुरी स्थित यूके नर्सिंग होम में आग लगी। पहली मंज़िल के स्टोर में लगी आग के बाद 28 मरीज़ों को दूसरी जगह किया गया शिफ्ट। इनमें 17 कोरोना मरीज़ भी थे।

20 मई, पंजाबी बाग़ स्थित ईएसआई अस्पताल की सातवीं मंज़िल पर आग लगी। मरीज़ों को दूसरी जगह करना पड़ा शिफ्ट।

16 जून, एम्स की नौंसी मंज़िल स्थित कंवर्जेंस ब्लॉक में आग लगी। कोई हताहत नहीं। दूसरे स्थान पर शिफ्ट किए गए रोगी।

27 जून, एम्स के आपातकालीन के पास बने स्टोर में लगी आग, लाखों का नुकसान।

27 जून, सफदरजंग अस्पताल की कैंटीन में लगी आग। कोई हताहत नहीं।

आग लगने की स्थिति में जल्द से जल्द राहत और बचाव कार्य शुरू करने के लिए यह कवायद की जा रही है। इससे किसी भी आपातकालीन स्थिति में कम समय में बचाव का कार्य शुरू किया जा सकेगा निश्चित ही इस योजना से फायदा होगा। ❑❑

अब रविवार को भी मरीज़ों के लिए खुलेगा बाह्य रोगी विभाग

दिल्ली में मरीज़ों के लिए बड़ी राहत भरी ख़बर है। अब राष्ट्रीय राजधानी के कुछ अस्पतालों में रविवार यानि छुट्टी के दिन भी मरीज़ अपना इलाज करा सकेंगे। केन्द्र सरकार की ओर से संचालित राजधानी के सफदरजंग, राम मनोहर लोहिया (आरएमएल), लेडी हार्डिंग अस्पताल, सुचेता कृपलानी अस्पताल व कलावती सरन बाल चिकित्सालय में रविवार को भी ओपीडी (बाह्य रोगी विभाग) सेवा उपलब्ध होगी। यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान जारी कर दी।

इस संबंध में मंत्रालय की ओर से सात अक्तूबर को निर्देश जारी किए गए हैं। इसके बाद अस्पतालों ने अपने-अपपने यहां इस पर अमल संबंधी निर्देश दिए हैं। लेडी हार्डिंग अस्पताल के निर्देशक डॉ. राम चंद्र ने कहा है कि स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देश के तहत यह फैसला किया गया है कि अस्पताल में बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) की सेवा रविवार को भी खुली रहेगी। शुरुआत में इन अस्पतालों में चुनिंदा विशेषज्ञता वाले डॉक्टर बैठेंगे। आदेश में कहा गया है कि रविवार को बाल रोग विभाग, काय चिकित्सा, शल्य चिकित्सा विभाग, स्त्री रोग और हड्डी रोग विभाग की ओपीडी खुलेगी। मंत्रालय के मुताबिक ओपीडी के लिए पंजीकरण सुबह आठ बजे से साढ़े ग्यारह बजे तक होगा और डाक्टर सुबह नौ बजे से दोपहर एक बजे तक मरीज़ों को देखेंगे।

पत्र में कहा गया है कि 'दवा की दुकानें सभी सातों दिन खुलेंगी और आपात प्रयोगशाला सेवा उन मरीज़ों

बाक़ी पेज 11 पर

संपादकीय

शांति मिशन

समानता के अधिकार की रक्षा की जाए

पहले गुजरात, फिर पंजाब और फिर उत्तर प्रदेश, तीनों राज्यों में पिछले दिनों ऐसे राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं, जिन्हें कुछ ही माह बाद होने वाले चुनावों की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। गुजरात में भाजपा सरकार सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रही है जहां मुख्यमंत्री सहित सारे मंत्रिमंडल को बदल दिया गया है। बदलाव का आधार वोटों के जातीय समीकरणों को बताया जा रहा है और इस बदलाव के ज़िम्मेदार लोग चाहते हैं कि मतदाता तक यह संदेश जाए कि सत्तारुढ़ दल उसकी जातीय भावनाओं के प्रति संवेदनशील है।

पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी। वहां भी चुनाव की दृष्टि से जातीय समीकरण साधे गए हैं और राज्य में पहली बार किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाया गया हैं मंत्रिमंडल के चयन में भी इस बात का ध्यान रखा गया है कि (निचली जाति) वालों को यह लगे कि कांग्रेस पार्टी उनके हितों के प्रति संवेदनशील है। संवेदनशीलता का ऐसा ही दिखावा उत्तर प्रदेश में योगी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने भी करना ज़रूरी समझा है। वहां मंत्रिमंडल का विस्तार करके पिछड़ों को कुर्सियों पर बिठाया गया है ताकि वोटरों के जातीय गणित से मतदाता को बरगलाया जा सके। इन तीनों राज्यों में इस उलटफेर का क्या परिणाम निकलता है, यह तो आने वाले चुनाव नतीजों से ही पता चलेगा, पर इस क़वायद से यह तो पता चल ही गया है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां यह मानकर चल रही हैं कि देश का मतदाता इतना भोला है कि वह राजनीतिक दलों की इस चाल का आसानी से शिकार बन जाएगा। वैसे हक़ीक़त भी यही है। यह दुर्भाग्य ही है कि चुनाव-दर-चुनाव हमने मतदाताओं को सत्ता लोभी राजनीतिक दलों के फैलाए जाल में फंसते देखा है। मज़े की बात यह है कि यह बीमारी सिर्फ इन दो बड़े दलों तक ही सीमित नहीं, देश के लगभग सभी दल जातीयता के लालच में लिप्त दिखाई दे रहे हैं। राजनीति में जातीयता की पूरी बिसात बिछाने के बावजूद केन्द्र की भाजपा सरकार देश की जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं है।

यह सही है कि समता, न्याय और बंधुता के घोषित आधारों वाले हमारे संविधान में जाति के आधार पर किसी को ऊंचा या नीचा समझना एक अपराध माना गया है, पर दुर्भाग्य यह भी है कि राजनीतिक दल तो चुनावी लाभ के लिए इस भेदभाव का सहारा ले ही रहे हैं, वहीं यह जातिगत वर्गीकरण हमारे सामाजिक सोच में भी दीमक की तरह अपनी जगह बनाए हुए हैं।

उत्तर प्रदेश की हाल ही की घटना है। मैनपुरी जिले के एक गांव दीमापुर में सरकारी स्कूल में तथाकथित अगड़ी और पिछड़ी जातियां आमने-सामने खड़ी हैं। स्कूल में विद्यार्थियों को दिए जाने वाले भोजन के लिए अगड़ों और पिछड़ों के लिए अलग-अलग बर्तन है। यह बर्तन न केवल अलग रखे जाते हैं बल्कि पिछड़ी जाति के छात्र छात्राओं को अपने बर्तन साफ भी खुद ही करने पड़ते हैं। विद्यार्थी भले ही इस भेदभाव को चुपचाप स्वीकार किए रहे हों, पर गांव के कुछ लोग इस स्थिति को और नहीं सह पाए। आवाज़ उठी!

स्कूल की अगड़ी जाति वाली मुख्य अध्यापिका को निलंबित कर दिया गया। होना तो यह चाहिए था कि सामाजिक समता की दिशा में उठाए गए इस क़दम के बाद स्थिति सुधर जाती, पर ऐसा हुआ नहीं। विवाद बढ़ गया मुख्य अध्यापिका के निलंबन के विरोध में गांव के अगड़ी जाति वाले उठ खड़े हुए। उन्होंने घोषणा कर दी जब तक निलंबन का यह आदेश वापस नहीं लिया जाता, अलग अलग बर्तन वाली व्यवस्था फिर से लागू नहीं होती, वे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। यह पंक्तियां लिखे जाने तक स्थिति यही बनी हुई है और यह स्थिति आज़ादी पा लेने के 75 वर्ष बाद की है। यह एक हक़ीक़त है कि आज़ादी की लड़ाई देश ने एक होकर लड़ी थी।

सभी जातियों, सभी वर्गों, सभी धर्मों के लोगों का योगदान था इस लड़ाई में। फिर हमने अपना संविधान बनाया जो देश के हर नागरिक को समानता का अधिकार देता हैं जनतांत्रिक मूल्यों का तकाज़ा है कि समानता के इस अधिकार की हर क़ीमत पर रक्षा की जाए। पर यह विडंबना ही है कि आए दिन दिमापुर गांव जैसी घटनाएं देश के अलग-अलग हिस्सों में घटती रहती हैं। नानक और कबीर से लेकर महात्मा गांधी और बाबा साहेब आंबेडकर तक की एक लंबी परंपरा है हमारे यहां उन महापुरुषों की जिन्होंने सामाजिक समरसता का संदेश पहुंचाया है। फिर हम तो वसुधैव कुटुंबकम की दुहाई भी देते है। जब सारी धरती एक कुटुंब है तो अगड़ी और पिछड़ी का क्या अर्थ रह जाता है? परिवार का दायित्व बनता है कि यदि कोई पीछे रह गया है तो उसका हाथ पकड़कर आगे लाया जाए। हमारी विडंबना यह है कि पीछे रह जाने वालों के पीछे रहने में ही हमें अपना लाभ दिखाई देता है। समानता के मार्ग पर इन 75 वर्षों में हम बहुत आगे बढ़ गए होते, पर हमारे सामाजिक और राजनीतिक नेतृत्व को किसी के पिछड़ेपन का लाभ उठाने की आदत पड़ गई है। लाभ नहीं, इसे ग़लत लाभ कहा जाना चाहिए। इस प्रवृत्ति के चलते प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री यह घोषणा करने में शर्म महसूस नहीं करते कि उनके मंत्रिमंडल में कितने सदस्य पिछड़ी जातियों के हैं। उन्हें लगता है कि यह संख्या दिखाकर वे मतदाताओं को भ्रमित कर सकते हैं। दुर्भाग्य से, ऐसा हो भी रहा है। अन्यथा चुनाव से ठीक पहले किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाकर या फिर मंत्रिमंडल में दलितों को स्थान देकर चुनावी लाभ उठाने की प्रवृत्ति क्यों पनप रही है?

राजनेताओं को इस प्रक्रिया में लाभ मिलने की आशा का सीधा सा मतलब यह है कि वे मतदाताओं को बरगलाने में सफल होते हैं। यह देश के जागरुक और विवेकशील मतदाताओं को तय करना है कि वह राजनेताओं के धोखे में नहीं आएंगे। पिछड़ों को अवसर मिलना चाहिए, यह उनका अधिकार है, पर यदि किसी को यह लगता है कि यह अधिकार देने की दुहाई देकर वह उपकार कर रहा है तो यह शर्म की बात हे। यह बात हमारे नेताओं को भी समझनी है और हमें भी।❑❑

तारीख़े इस्लाम

ख़ुतबाते सीरते तैयिबा

मुफ़्ती मुहम्मद सलमान मंसूरपुरी क़िस्त- 96

ग़ज़वा-ए-हुनैन

सन 8 हिजरी में मक्का मुअ़ज़्ज़मा फ़तह हो गया, उसके क़रीब में कुछ क़बाइल ऐसे थे जो अपने को बहुत ताक़तवर समझते थे, उन में हवाज़िन और सक़ीफ़ के लोग मशहूर थे, जब उनको पता चला कि मक्का मुअ़ज़्ज़मा फ़तह हो चुका है, तो उन्होंने पैग़म्बर अ़लैहिस्सलाम से मुक़ाबले के लिए तैयारियाँ शुरू कर दीं, और अजीब इत्तिफ़ाक़ यह हुआ कि उन के सरदार मालिक बिन औ़फ़ के दिल में यह बात आई कि अगर हम सिर्फ़ मर्दों को जंग में ले जायेंगे तो उनका दिल औ़रतों और अपने माल व दौलत में अटका रहेगा, तो उस ने यह हिमाक़त की कि अपने लश्कर के साथ तमाम औ़रतों को भी जंग में शरीक किया, और माल व दोलत, हज़ारों ऊँट बकरियों और सोने चाँदी के साथ निकल पड़े, और अपने दिल में यह सोचा कि अब लोग डट कर लड़ेंगे, उन में एक माहिर ज़ंग ''दुरैद बिन सम्मा'' भी था, जो बुढ़ापे के बिल्कुल आख़िरी स्टेज पर था, उस ने बहुत मना किया कि यह तो ग़लत बात है, अ़क़लमंदी की बात नहीं है, लेकिन लोगों ने ख़ुद उसी को बेवक़ूफ़ बनाया और कहा कि तुम्हारी अक़ल तो बूढ़ी हो चुकी है। (अल-रौज़ुल अनफ़ जि. 4 स. 205, ज़ादुल मआ़द मुकम्मल 705)

नबी-ए-अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़तहे मक्का के बाद 19 रोज़ मक्का मुअ़ज़्ज़मा में क़याम फ़रमाया। (बुख़ारी शरीफ़, 2/615) और 6 शव्वाल को उन लोगों से मुक़ाबला के लिए तशरीफ़ ले चले, 12 से 14 हज़ार अफ़राद तक आप के साथ थे और बहुत जोशीले अंदाज़ में थे, तो कुछ लोगों के ज़ेहन में यह बात आ गई कि आज तो हम उनका क़ीमा बना देंगे, क्योंकि जब हम 313 थे, उस वक़्त उनको सबक़ सिखला दिया, और उहुद व ख़ंदक़ के मौक़े पर भी उनको शिकस्ते फ़ाश दी तो आज हमें कौन हरा सकता है, तो अल्लाह तआ़ला को यह बात पसंद नहीं आई। जब इस्लामी फ़ोर्स ऐसी जगह से गुज़र रही थी जो दो पहाड़ियों के दरमियान से होकर गुज़रती है तो क़बीला हवाज़िन के तीर अंदाज़ों ने दोनों जानिब छुप कर तीरों की बौछार कर दी जिस से फ़ौज के अगले हिस्से में खलबली और भगदड़ मच गई, अल्लाह तआ़ला ने यह दिखलाया कि अपनी तादाद पर इतराना तुम्हें ज़ेब नहीं देता है, फ़ौज की तादाद पर नहीं बल्कि अल्लाह तआ़ला की मदद और नुसरत पर नज़र होनी चाहिये। (ज़ादुल मआ़द मुकम्मल 706)

क़ुरआन पाक में अल्लाह ने इसको ज़िक्र फ़रमाया:

''अल्लाह ने तुम्हारी बहुत सी जगहों पर मदद की है और हुनैन के दिन भी मदद की है, जब तुम्हारी कसरत तुम्हें अच्छी लगी, उस कसरत ने तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं दिया, ज़मीन तुम्हारे ऊपर तंग हो गई और तुम्हारे पैर उखड़ गए।''

इस ख़तरनाक मरहले पर दुनिया ने एक अजीब मंज़र यह देखा कि जब तमाम लोगों के पैरों तले से ज़मीन निकल रही थी, तो सरकारे कायनात फ़ख़रे दो आलम मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम अपनी जगह पर साबित क़दम थे, और आप फ़रमा रहे थे:

''मैं ही नबी हूँ इस में कोई झूठ नहीं है, और मैं अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में से हूँ।''

फिर आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हज़रत अ़ब्बास रज़ि अल्लाहु अ़न्हु से फ़रमाया कि पुकारो:

(अनसार कहाँ है?) तो जिस अनसारी सहाबी के कान में यह आवाज़ पड़ी, वह वहीं से वापस आ गया, और एक भीड़ सी जमा हो गई, फिर आप ने आवाज़ लगाई।

(मुहाजिरो! कहाँ जा रहे हो?) यह सुनते ही वह भी सब पलट गए और फिर जो ज़बरदस्त जंग हुई है, चंद ही लम्हों में मुक़ाबिल दुश्मन में भगदड़ मच गई। (मुस्लिम शरीफ़, 2/100) और वह अल्लाह की नुसरत और मदद की ताब नहीं ला सका, इस जंग में दुश्मन के 6 हज़ार अफ़राद क़ैदी बना लिए गये, 24 हज़ार ऊँट माले ग़नीमत में हाथ आए, 40 हज़ार से ज़्यादा बकरियाँ हाथ आई, कुफ़्फ़ार 6 कुन्टल से ज़्यादा चाँदी अपने साथ लाए थे, वह भी मुसलमानों के क़ब्ज़े में आई, नबी-ए-अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने यह तमाम माल फ़ौरन तक़सीम नहीं किया, बल्कि कुछ दिन इन्तिज़ार फ़रमाया, इसके बाद आप ने मुक़ामे जअ़्राना (जहाँ से बड़ा उमरा किया जाता है) पर क़याम फ़रमाया, और माले ग़नीमत तक़सीम करना शुरू किया, जो बड़े बड़े क़ुरैशी सरदार नये नये इस्लाम लाये थे, आप ने एक एक को 100-100 ऊँट दिए, और बहुत सी चाँदी दे दी ताकि उनका ईमान मज़बूत हो जाए।

जब आप तक़सीम फ़रमा रहे थे, तो अंसार के नौजवानों को यह बात अच्छी नहीं लगी, उनकी ज़बान से यह जुमला निकला कि :''जब ख़ून की ज़रूरत पड़ती है तो हमें बुलाया जाता है, और जब माल तक़सीम करने का नम्बर आया, तो अपने लोगों को तक़सीम कर रहे हैं''।

नबी अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को जब यह जुमला पहुंचा तो आप ने उन लोगों को जमा फ़रमाया और तहक़ीक़ की कि ''क्या किसी ने यह कहा है''? उन लोगों ने कहा कि हज़रत! नौजवानों की ज़बान पर यह बात आ गई थी, लेकिन जो सूझ बूझ के लोग हैं उनके दिल में ऐसा कोई ख़्याल नहीं है। (जारी)

किसान राजनीति कर रहा है तो ग़लत क्या है राज की नीति का विरोध पाप तो नहीं है

सोमपाल शास्त्री

सोमपाल शास्त्री अटली बिहारी वाजपेयी की सरकार में कृषिमंत्री थे। राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। वेस्ट यूपी के कद्दावर जाट परिवार से आते हैं। 1998 के लोकसभा चुनाव में चौधरी अजीत सिंह जैसे दिग्गज को हराकर लोकसभा में पहुंचे थे। हालांकि अब वह भाजपा में नहीं है , लेकिन जब कृषि कानूनों को लेकर किसानों ने आंदोलन की राह पकड़ी तो केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र तोमर ने सबसे पहले सोमपाल शास्त्री से मुलाकात की थी। पेश है सोमपाल शास्त्री जी हुई एक बातचीत के प्रमुख अंश :-

प्रश्नः- कृषि क़ानूनों की वापसी की मांग पर किसान संगठनों और सरकार के बीच पहले से गतिरोध बना हुआ है। लखीमपुर की घटना से मौजूदा आंदोलन को किस ओर जाता हुआ देख रहे हैं?

उत्तरः- मुझे नहीं लगता है कि यह आंदोलन किसी हल की ओर बढ़ रहा है। इसका एक कारण तो सरकार की हठधर्मिता है। दूसरा सरकार और किसानों के बीच विश्वास का संकट है। इसकी पृष्ठभूमि 2014 के चुनाव अभियान से शुरू होती है, जब भाजपा ने किसानों के हक़ में कई बड़े वायदे किए थे, जिनमें एक था स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाएगा। चुनाव में इसका फायदा भी भाजपा को मिला। लेकिन सरकार में आने पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि मौजूदा आर्थिक संसाधनों में ऐसा कर पाना संभव नहीं है। जब 2019 का चुनाव आने वाला हुआ तो इन्होंने घोषणा कर दी कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया है। खेल यह हुआ कि स्वामीनाथन ने सी-2 स्तर की लागत में 50 प्रतिशत जोड़ने की बात कही है, सरकार ने एक लेवल नीचे ए-2+एफएल पर जोड़ा। 2016 में एक और घोषणा की कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना कर दिया जाएगा। लेकिन सरकारी आंकड़े कहते हैं कि किसानों की वास्तविक आय 2013 की तुलना में 2020 में 35 से 42 प्रतिशत कम हुई है।

प्रश्नः- मौजूदा विवाद नए कृषि क़ानूनों को लेकर है। किसान संगठन कानून वापसी चाहते हैं। सरकार का कहना है कि क़ानून के जिन बिंदुओं पर आपत्ति हो, वह बताओ हम दूर करने को तैयार हैं। यह गतिरोध कैसे दूर हो सकता है?

उत्तरः- मैं अटलजी की सरकार में मंत्री रहा हूं। कैबिनेट की मीटिंग में यह जरूरी नहीं होता था कि जो बात अटल जी को पसंद हो, वही बोली जाए या कोई चर्चा ही न हो। तमाम उदाहरण हैं कि कैबिनेट में अटल जी की राय कुछ और होती थी, मंत्रीगण की राय कुछ और, लेकिन खुलकर विमर्श होता था, उस विमर्श से ही नया रास्ता निकलता था। अपनी राय कुछ और होने के बावजूद अटल जी उचित राय को स्वीकार करते थे। अब मैं समझता हूं कि परस्पर चर्चा और परामर्श की परंपरा समाप्त हो गई है। ऐसे में कोई रास्ता कैसे निकलेगा?

प्रश्नः- जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था तो केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमन ने आपसे मुलाकात की थी, आपने उन्हें क्या सलाह दी थी?

उत्तरः- मैंने उनसे कोई गोपनीय बात नहीं की थी। मैं सार्वजनिक मंच से जो कहता आ रहा हूं, वही उनसे भी कहा था। पहली यह कि जब किसानों को ये क़ानून अपने फायदे में नहीं लग रहे हैं तो ज़बरदस्त क्यों? दूसरी बात जिन जिंसों का सरकार समर्थन मूल्य घोषित करती है, वह मूल्य उन्हें दिलवाना भी सुनिश्चित करे। इससे भी बड़ी बात यह है कि अभी तक उन 22 जिंसों का ही समर्थन मूल्य घोषित होता है जो भंडारण योग्य हैं लेकिन जिनका योगदान कृषि के सकल घरेलू उत्पाद में मात्र 30 प्रतिशत है। 70 प्रतिशत पेरिशेबल कमोडिटी होती है जैसे फल, सब्जी, दूध, पोल्ट्री जिनके दाम सबसे ज़्यादा क्रैश करते हैं। इनके लिए भी न्यूनतम मूल्य तय होना चाहिए। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाए ताकि उसकी सिफारिशें सरकार के ऊपर बाध्यकारी हों।

प्रश्नः- सरकार का कहना है कि कृषि क़ानूनों को लेकर जो विरोध है वह किसानों का नहीं है, महज़ कुछ नेताओं का है। क्या इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है?

उत्तरः- यह बात कहना ग़लत है कि आंदोलन में किसान नहीं है। अगर किसान नहीं शामिल होता तो यह आंदोलन इतना लंबा चल ही नहीं सकता था। अब रही बात राजनीति की तो इस मुद्दे पर राजनीति किसने शुरू की? शुरुआत तो सरकार ने ही की। क़ानून लागू करने के लिए सदन की प्रतीक्षा भी नहीं की गई। असाधारण स्थिति बताते हुए अध्यादेश लाया गया और अगर किसान राजनीति कर भी रहे हैं तो इसमें ग़लत क्या है? राज की नीति का विरोध कोई पाप तो नहीं हैं।

प्रश्नः- जिन तीन कृषि क़ानूनों पर इतना विवाद है, उनको लेकर आपका क्या नज़रिया है.?

उत्तरः- 1990 में जो भानु प्रताप कमेटी बनी थी, वह मेरे ही कहने पर बनी थी। उसने ये तीनों ही सिफारिशें की थीं लेकिन उनके साथ तीन शर्तें जुड़ी हुई थीं। पहली न्यूनतम खरीद मूल्य को कानून अधिकार बनाया जाए। दूसरी न्यूनतम समर्थन मूल्य सभी जिंसों और सभी किसानों के लिए हों। तीसरी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। अगर सरकार ये बातें मान लेते हैं तो क़ानून रहें अथवा न रहें उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। ❑❑

पुलिस के लिए पब्लिक का भरोसा जीतना ज़रूरी है : सागर प्रीत हुड्डा

प्रश्नः- यमुनापार के तीनों जिले उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे हैं इस इलाक़े की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से क्या एहतियात बरती जाती है?

उत्तरः- उत्तर प्रदेश बार्डर का इलाक़ा सटा होने से दोनों ओर से अपराधी वारदात को अंजाम देने के बाद एक दूसरे के एरिया में छिप जाते हैं इसलिए सभी हिस्ट्रीशटर को सर्विलांस पर रखा जाता है। कमिश्नर साहब की पहल के बाद पीसीआर स्टाफ को थाने के साथ मर्ज़ किया गया है। इससे पुलिस की एरिया में विजिबिलिटी बढ़ी है। इसके अलावा यूपी पुलिए के साथ मिलकर ऑपरेशन करते हैं। अपास में क्रिमिनल्स की लिस्ट सांझा करते हैं। ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। लोनी से लेकर नोएडा तक का लंबा बार्डर है, जहां कई जगह परमानेंट रात दिन की पिकेट रहती है। कई जगह हम स्ट्रैटिजिक सरप्राइज पिकेटिंग भी करते हैं।

प्रश्नः- बार्डर क्रॉस कर छिपकर रहने वाले और यहां रहकर वारदातों को अंजाम देने वाले बदमाशों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस क्या कर रही है?

उत्तरः- रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन और मार्केट वेलफेयर एसोसिएशंस को किराएदारों का वेरिफिकेशन कराने के लिए कहा जाता है। समय-समय पर पिकेट चेकिंग करते हैं। किस टाइम पर किस एरिया में ज़्यादा क्राइम हो रहा है, इसे एनलाइज किया जाता है। इसके हिसाब से पेट्रोलिंग बढ़ाई जाती है और पिकेट चेकिंग की जाती है। नाइट पेट्रोलिंग में भी इज़ाफा किया जाता है। पैदल, बाइक और गाड़ी से पेट्रोलिंग बढ़ाई जाती है।

प्रश्नः- यमुनापार में झपटमारी और गाड़ी चोरी के जो मामले सामने आ रहे हैं, उन पर अंकुश लगाने के लिए आपकी क्या योजना है.?

उत्तरः- ईस्ट दिल्ली काफी घनी आबादी वाला इलाक़ा है। यूपी वाला इलाक़ा भी इसी तरह का है। इसलिए यहां पर काम करना काफी चैलेंजिंग है। स्नैचिंग को लेकर हम इंटेलिजेंस बेस्ट काम करते हैं। पहले कभी वारदातों में शामिल रहे बदमाशों को सर्विलांस पर रखा जाता है। पिकेटिंग और पेट्रोलिंग भी समय समय पर बदलाव किया जाता है। हॉट-स्पॉट

पब्लिक का पुलिस पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। हमारे लिए उनका विश्वास जीतना अहम होता है। इसलिए हर पुलिस स्टेशन में ऐसे काम किया जाता। इसी कड़ी में हर शनिवार को सब डिविजन लेवल पर सुनवाई का आयोजन किया जा रहा है। एसीपी लेवल के अधिकारी पब्लिक की शिकायतों को सुनकर निवारण करते हैं।

एरिया की पहचान की जाती है, जहां पर पुलिस की ज़्यादा तैनाती की जाती है। इनपुट मिलने पर ट्रैप लगाए जाते हैं और बदमाशों को पकड़ा जाता है। गाड़ियों में टू व्हीलर की ज़्यादा चोरी होती है। छोटी-छोटी गलियां और कई कॉलोनियों में गेट नहीं हैं। ऐसे में आरडब्ल्यूए से कॉलोनी में रात को एंट्री और एग्जिट पाईंट कम करने के लिए कहते हैं। गार्ड की तैनाती और सीसीटीवी कैमरों को लगाने के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं। इससे क्राइम साल्व करने में मदद मिलती है।

प्रश्नः- नार्थ ईस्ट जिले में कई गैंग ऑपरेट हो रहे थे। गैंग ऑपरेट मकोका के तहत जेल में है, लेकिन उनके कई गुर्गे फरारी काट रहे हैं। उन्हें पकड़ने के लिए क्या किया जा रहा है?

उत्तरः- कमिश्नर साहब की ओर से गैंगस्टर्स के ख़िलाफ़ सख़्त एक्शन लेने के निर्देश हैं। इस इलाक़े के पुराने सभी गैंगस्टर्स जेल में हैं। इनके कुछ सहयोगी वांटेड हैं, जो फिलहाल एरिया से फरार हैं। इन्हें पकड़ने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है। सभी फरारी काट रहे आरोपियों की गिरफ्तारी की कवायद चल रही है। जल्द ही इन सभी को पकड़ लेंगे। एरिया के लोग अगर किसी गैंग से जुड़े व्यक्ति की गतिविधि के बारे में सूचना देते हैं या फिर कोई खुद को किसी गैंस से जुड़ा बताकर अपराध करने की कोशिश करता है तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाता है।

प्रश्नः- पुलिस पर आम जनता भरोसा करे, इसके लिए कैसे प्रयास किए जा रहे हैं?

उत्तरः- पब्लिक का पुलिस पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। हमारे लिए उनका विश्वास जीतना अहम होता है। इसलिए हर पुलिस स्टेशन में ऐसे काम किया जाता। इसी कड़ी में हर शनिवार को सब डिविजन लेवल पर सुनवाई का आयोजन किया जा रहा है। एसीपी लेवल के अधिकारी पब्लिक की शिकायतों को सुनते हैं और उनका निवारण करते हैं। कभी-कभी डीसीपी और ज्वाईंट सीपी लेवल के अफसर भी जन सुनवाई में शिरकत करते हैं। आरडब्यू, एमडब्ल्यू और अमन कमेटी की मीटिंग होती है। माननीय सांसदों की चेयरमैनशिप में जिला कमिटियों की मीटिंग होती है। कम्यूनिटी पुलिसिंग के तहत युवा, निर्भीक, सशक्ति और परिवर्तन प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। ❑❑

राज्यों द्वारा बनाए जाने वाले क़ानूनों पर बहस आवश्यक

भारत ग्रेट ब्रिटेन द्वारा जारी कॉलम लॉ प्रणाली का अनुसरण करता है हालांकि भारत ने एक स्वतंत्र राष्ट्र होने के नाते अपने क़ानून में नयापन लाने की कोशिश की और इसमें से एक साबित करने की जिम्मेदारी को पलटना शामिल है। भारत में अनेकों आपराधिक कानूनों तथा विशेषकर वे कानून जो 2014 के बाद अस्तित्व में आए, उनमें साबित करने की जिम्मेदारी को पलटा गया है। इसका मतलब यह है कि यहां पर दोष की संभावना है। सरकार मानती है कि आपने कुछ ग़लत किया है और ख़ुद को बेगुनाह साबित करना होगा।

साधारण आपराधिक क़ानून का यह बिल्कुल विपरीत ढंग है। मिसाल के लिए यदि कोई एक शव के साथ चाकू को पकड़े पाया जाता है तो यह सरकार के लिए है कि वह यह साबित करे कि व्यक्ति ने हत्या को अंजाम दिया है हालांकि यहां पर ऐसे क़ानून भी है जिनमें सरकार दोष की धारणा के साथ शुरुआत करती है। ऐसी एक मिसाल में असम में नेशनल रजि॰ ऑफ सिटीजंस शामिल है।

असम में सभी को सरकारी दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करना था जिनमें यह दर्शाना था कि उनके पूर्वज 1971 से पहले नागरिक के तौर पर असम में रहते थे, जो सरकारी ट्रिब्यूनलों के समक्ष नहीं आए तथा प्रमाणित के वे वैध हैं। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उन्हें जेलों में बंद कर दिया गया। आज इसी के चलते जेलों में सैकड़ों लोग बंद हैं और ज़्यादा जेलों का निर्माण किया जा रहा है। ब्रिटिश क़ानूनों का कहना है कि जहां एक ओर प्रतिवादी पर क़ानूनी तौर पर साबित करने की ज़िम्मेदारी है तो उन्हें उचित संदेह से परे मुद्दे को साबित करने की ज़रूरत नहीं। भारत में क़ानून ऊंचा है और यह बात का हर्ष असम तथा अन्य क्षेत्रों में देख सकते हैं।

भारत ने अनेकों भाजपा शासित राज्यों में धार्मिक क़ानूनों की स्वतंत्रता का क़ानून बनाया है। धर्मांतरण के लिए साबित करने की जिम्मेदारी को पलटा गया है। कानून को पहली बार 2018 में उत्तराखंड में पास किया गया था तथा उसके बाद हिमाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलिजन एक्ट 2019 लाया गया। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म समपरिवर्तन प्रतिषेद अध्यादेश 2020 (धार्मिक अध्यादेश के ग़ैर क़ानूनी ध र्मांतरण निषेद), मध्य प्रदेश स्वतंत्रतीय अध्यादेश, 2020 (धार्मिक अध्यादेश की स्वतंत्रता) तथा गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलिजन (संशोधन) एक्ट, 2021 लाया गया।

यह क़ानून हिन्दुओं तथा मुसलमानों के बीच शादी का अपराधीकरण करते हैं। क़ानूनों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति शादी के बाद या पूर्व धर्म परिवर्तित करता है तो सरकार शादी को अमान्य घोषित करती है। ऐसा बच्चों के होने के बावजूद भी किया जाता है।

साबित करने की ज़िम्मेदारी दर्शाती है धर्मांतरण कोई धोखाधड़ी नहीं है। सरकार को भेजे गए एक निवेदन के बिना अपना धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों को जेल में भेजा जाता है। इन क़ानूनों के बारे में एक अन्य विचित्र बात यह है कि यह हिन्दुओं पर लागू नहीं होते।

हिमाचल प्रदेश में मूल क़ानून का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति अपने पूर्व के धर्म में वापस लौटता है तो इसे धर्मांतरण नहीं माना जाना चाहिए। यह कानून पैतृक कानून का उल्लेख नहीं करते मतलब यह है कि यह क़ानून स्पष्ट है। जो लोग हिन्दू धर्म में परिवर्तित नहीं होते उन्हें सज़ा नहीं मिलेगी।

पिछले वर्ष सी.ए.ए. प्रदर्शनों के दौरान 21 प्रदर्शनकारियों को यू.पी. पुलिस के गोली मारे जाने के बाद उत्तर प्रदेश रिकवरी ऑफ डेमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रापॅर्टी एक्ट 2020 बनाया गया। यह क़ानून राज्य सरकार को सरकारी सम्पत्ति को क्षतिग्रस्त करने वाले कथित लोगों पर जुर्माना करने का अधिकार देता है। इसके अलावा ऐसे लोगों के घरों तथा उनकी सम्पत्तियों को ज़ब्त करने का अधि कार भी देता है और यदि अपराधी ट्रिब्यूनल के समक्ष पेश होने में असमर्थ होता है तो अटैचमेंट के लिए निर्देश पास किए जा सकते हैं जिनके बारे में कोई भी अपील नहीं की जा सकती।

2014 के बाद और क़ानून अस्तित्व में आए जिनमें गोहत्या पर साबित करने की ज़िम्मेदारी को पलटना भी है। ऐसे क़ानूनों को भाजपा शासित राज्य सरकारों ने भी पारित किया। इनमें महाराष्ट्र एनिमल प्रिजर्वेशन (अमैंडमेंड) एक्ट, 2015, हरियाणा गौवंश संरक्षण एवं गौ संवर्धन एक्ट, 2015, गुजरात एनिमल प्रिजर्वेशन (अमैंडमेंड) एक्ट, 2017, तथा कर्नाटक प्रिवैंशन ऑफ स्लाटर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कैटल शामिल हैं।

गौहत्या के लिए गुजरात में सज़ा एक आर्थिक अपराध है क्योंकि इसका मक़सद पशुपालन का संरक्षण करना है। इस क़ानून के तहत इसके लिए आपको उम्रभर जेल में रहना पड़ सकता है। कोई भी आर्थिक अपराध इस सज़ा को नहीं सुनाता। 2019 में एक नए कानून के तहत एक मुसलमान व्यक्ति को 10 वर्ष की जेल की सज़ा सुनाई गई। उस पर अपनी बेटी की शादी पर बीफ परोसे जाने का अपराध था। हालांकि पुलिस यह साबित नहीं कर पाई कि आख़िर ऐसा हुआ है। उस मामले में जज ने कहा कि यह व्यक्ति पर है कि वह साबित करे कि वह निर्दोष था क्योंकि खाया गया खाना टैस्ट नहीं किया जा सकता था इसलिए यह साबित नहीं हो सका और कोर्ट ने व्यक्ति को जेल भेज दिया। दिलचस्प बात यह है कि भाजपा ने अपने पूर्व के रूप में जनसंघ के तौर पर निवारक निरोधक क़ानूनों का विरोध किया था मगर आज यह ऐसे क़ानूनों की चैम्पियन हैं दूसरी बात नोट करने वाली यह है कि दोष की अवधारणा कानूनों की गिनती 2014 के बाद से बढ़ी है मगर उसका कोई विरोध नहीं हुआ और न ही उन पर कोई बहस ही हुई कि क्या हमारे पास ऐसे क़ानून होने चाहिएं या नहीं। ❑❑

रोज़गार .....

आर्कियालॉजिकी में भी है सुनहरा भविष्य

इतिहास अर्थात् बीते हुए समय की लम्बी दास्तान और इसी इतिहास को पूरे विश्व में विभिन्न दृष्टिकोणों से बार-बार परखा जाता रहा है। उनमें से कई दृष्टिकोण ऐसे हैं जो पूर्वाग्रहों की बुनियाद पर अपनाए जाते हैं और फिर फैक्टस या तथ्यों को तोड़-मरोड़कर उनका ऐसा इंटरप्रेटेशन किया जाता है कि झूठ सच की शक्ल ले लेता है। बीते हुए काल की व्याख्या में अक्सर मतभेद होते रहे हैं। इस समस्या का एकमात्र हल है आर्कियोलॉजी अर्थात् पुरातत्व विज्ञान, जिसका काम मौजूदा साक्ष्यों के आधार पर बीते हुए कल यानि इतिहास की सच्चाई उजागर करना है। यह सच बताने वाले लोग विशेष योग्यता हासिल होते हैं और इसमें युवाओं के लिए कैरिअर की बहुत चमकीली संभावनाएं विद्यमान हैं।

क्या है आर्कियोलॉजी

ध्यातव्य है कि आर्कियोलॉजी में एंथ्रोपोलॉजिकल अध्ययन किया जाता है, जिसके तहत प्राचीन मानव संस्कृति को खंगाला जाता है। आर्कियोलॉजी प्राचीन मानव के सांस्कृतिक आचार व्यवहार को व्याख्यायित करता है। इसके लिए पुरानी सभ्यताओं द्वारा छोड़ी गई चीज़ों गई और खंडहरों, उनकी गतिविधियों, व्यवहार आदि का अध्ययन करता है।

आर्कियोलॉजी ऐतिहासिक खोज की यह शाखा है, जो विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक हैं। इसमें प्राचीन अवशेषों से सामना होता है। मसलन प्राचीन सिक्के, बर्तन, चमड़े की किताबें, भोजपत्र पर लिखित पुस्तकें, शिलालेख मिट्टे के नीचे दफन शहरों के खंडहर या फिर पुराने क़िले, मंदिर, मस्जिद और हर प्रकार के प्राचीन अवशेष, वस्तुओं आदि का अध्ययन आर्कियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। आर्कियोलॉजीकल मान्यूमेंटस, आर्ट्स एण्ड क्राफ्ट्स, काईन, सील, बीड, लिट्रेचर और नेचुलर फीचर्स के संरक्षण एवं प्रबंध न का कार्य आर्कियोलॉजीकल के तहत आता है। आर्कियोलॉजीकल न केवल इन चीज़ों का ज्ञान रखता है बल्कि उनकी खोज भी करता है।

क्या होता है कार्यक्षेत्र

आर्कियोलॉजिस्ट प्राचीन भौतिक अवशेषों की खोज करते हैं, उनका अध्ययन/परीक्षण करते हैं और फिर अपने तार्किक निष्कर्ष के आधार पर इतिहास की सटीक व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। इस प्रक्रिया के कारण जहां एक ओर दुनिया को इतिहास की सही जानकारी प्राप्त होती है वहीं अंधविश्वास और ग़लतफहमियों का निपटारा भी इस प्रकार की महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोजों से संभव होता है। समय-समय पर पुरातात्विक दस्तावेज़ और वस्तुएं खोजी जाती रही हैं जो विगत का सही-सही लेखा जोखा प्रस्तुत करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है और हमें और अधिक वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करती है। आर्कियोलॉजकल साइंस हमें ऐतिहासिक अधंविश्वासों और पूर्वाग्रहों से निजात दिलाकर वास्तविक दृष्टिकोण प्रदान करता है।

कैसे बढ़ें आगे

अगर आप इतिहास को खंगालने के शौकीन हैं और इसके ज़रिए कई तरह की नई चीज़ों का पता लगाना चाहते हैं तो आर्कियोलॉली के क्षेत्र में आपके लिए केरिअर की बहुत उजली संभावनाएं हैं। आर्कियोलाजी में कैरिअर बनाने के लिए उन विद्यार्थियों को आगे आना चाहिए जो लुप्त समाज, सभ्यताओं उनके इतिहास तथा अवशेषों के बारे में जानने में गहरी रुचि रखते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको तीन वर्षी डिग्री (बीए इन आर्कियोलाजी) करनी होगी, जिसके लिए 12वीं स्तर पर एक विषय के रूप में इतिहास की पढ़ाई आवश्यक है। यदि आगे आप एमए इन आर्कियोलॉजी करना चाहते हैं, तो इसकी न्यूनतम योग्यता बीए इन आर्कियोलॉजी या समकक्ष है। इस क्षेत्र के लिए कम्युनिकेशन और आईटी स्किल की भी बहुत ज़रूरत है।

प्रमुख संस्थान

स्कूल ऑफ अर्काइवल स्टडीज, नेशनल आर्काइवज ऑफ इंडिया, जनपथ नई दिल्ली। स्नातक और स्नातकोत्तर पाठयक्रम के लिए :-

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार। गुजरात विद्यापीठ, आश्रम रोड, अहमदाबाद। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी। कोलकाता विश्वविद्यालय, सीनेट हाउस, 87 कॉलेज स्ट्रीट कोलकाता। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, गढ़वाल उत्तराखंड। पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र दिल्ली इंस्टीटयूट ऑफ हेरिटेज रिसर्च एंड मैनेजमेंट नई दिल्ली। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्व विद्यालय, अजमेर। जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर। डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर। ❑❑

इस्लामी दुनिया

पाक : जनरल बाजवा की पसंद अंजुम बने आईएसआई प्रमुख

इस्लामाबाद: पाकिस्तान में खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) के प्रमुख की नियुक्ति को लेकर पिछे कुछ समय से प्रधानमंत्री इमरान ख़ान और सैन्य प्रमुख क़मर जावेद बाजवा के बीच जारी द्वंद्व पर विराम लग गया। दोनों के बीच हुई बैठक के बाद पाकिस्तान ने लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को आईएसआई चीफ नियुक्त किया है। पाकिस्तान के एक समाचार चैनल ने इसकी पुष्टि की है।

तालिबान को चीन ने दिए दस लाख डॉलर, आगे 50 लाख डॉलर का वादा

काबुल : तालिबान के साथ उच्च स्तरीय दोहा वार्ता के बाद चीनी विदेश मंत्री वांग यी और तालिबान के उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल ग़नी बरादर के बीच हुई मुलाकात के अगले तालिबान प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने बताया, चीन ने अफग़ानिस्तान को 10 लाख डॉलर (साढ़े सात करोड़ रुपये) दिए हैं। इसके अलावा उसने सरकार को मानवीय सहायता के तहत दवा भोजन के लिए 50 लाख डॉलर (साढ़े 37 करोड़ रुपये) और देने का वादा किया है। यी और बरादर के बीच यह दूसरी मुलाक़ात थी। इस बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने तालिबान में राजनीतिक और आर्थिक हालात पर चर्चा की।

बांग्लादेश : हिन्दुओं से हिंसा के बाद क़ानून

ढाका : बांग्लादेश में पिछले दिनों सोशल मीडिया पर झूठी पोस्ट के बाद भड़की हिंसा के बाद देश के क़ानून मंत्री अनीसुल हक़ ने कहा कि सरकार बहुत जल्द एक नया क़ानून बनाने जा रही है। इसके तहत किसी भी मामले में गवाही देने वालों की सुरक्षा और उनकी गोपनीयता सुनिश्चित की जाएगी। गवाहों पर क़ानून हिन्दुओं पर हुए हमलों मद्देनज़र बनेगा।

मस्जिद में फायरिंग, 18 नमाज़ियों की हत्या

लागोस : उत्तरी नाइजीरिया में पिछले दिनों सुबह की नमाज़ के दौरान एक मस्जिद पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया, जिसमें 18 नमाज़ियों की मौत हो गई। यह हमला देश के नाइजर के माशेगू स्थानीय सरकारी क्षेत्र के माजकुका गांव में हुआ। हमलावरों के जातीय फुलानी खानाबदोश चरवाहा समुदाय से होने का संदेह है, जो घटना के बाद मौक़े पर फरार हो गए। इसी तरह की जातीय हिंसा में इस वर्ष अब तक सैकड़ों लोगों की जान गई है। जातीय हिंसा की ये घटनाएं देश में पानी और ज़मीन के मुद्दे को लेकर दशकों से चल रहे संघर्ष का नतीजा है। संघर्ष का शिकार बने फुलानी समुदाय के कुछ लोगों ने स्थानीय होसा कृषक समुदाय के लोगों के ख़िलाफ़ हथियार उठा लिए हैं।

चुनौती समान अवसर की

सुशील कुमार सिंह

समान अवसर न केवल लोकतंत्र की बुनियादी कसौटी होते हैं, बल्कि सुशासन की चाह रखने वाली सरकारों के लिए दक्ष और सफल सरकार बनने का पहला अध्याय भी हैं। सभी के लिए समान अवसर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र मानवतावादी दृष्टिकोण है और यही संदर्भ शासन और प्रशासन को सामाजिक सुशासन की ओर बढ़ाता है। ग़ौरतलब है कि सुशासन सामाजिक-आर्थिक न्याय की सर्वोच्च उपलब्धि होता है और लोक सशक्तिकरण इसके केन्द्र में होता है। इसके मूल में धारणा यही होती है कि समाज का प्रत्येक तबक़ा सुशासन का अनुभव करे और उसका जीवन खुशी और शांति से परिपूर्ण हो। यह अतिश्योक्ति नहीं कि संविधान स्वयं में एक सुशासन है और इसी संविधान के भाग-4 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों में सामाजिक आर्थिक स्थितियों का भरपूर निधरिण है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से ओत-प्रोत यह हिस्सा न केवल सामाजिक सुशासन को प्रतिष्ठित करने में योगदान देता है, बल्कि राज्य सरकारें सचेतता के साथ कुछ भी बाकी न छोड़ें, इस ओर ध्यान भी केन्द्रित करता है।

नीति निर्देशक तत्वों के हर अनुच्छेद में गांधी दर्शन का भाव नीहित है। अनुच्छेद 38, 41, 46 और 47 इस मामले में विशेष रूप से प्रासंगिक देखे जा सकते हैं। अनुच्छेद 38 के विन्यास को समझें तो यह जनता के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था क़ायम रखना, अनुच्छेद 41 काम के अधिकार, शिक्षा के अधिकार और लोक सहायता पाने का अधिकार के निहित भाव को समेटे हुए हैं, जबकि अनुच्छेद 46 कमज़ोर तबक़ों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की बात करता है। अनुच्छेद 47 यह ज़िम्मेदारी सुनिश्चित करता है कि जनता के पोषण और जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जाए। हालांकि भाग-4 के भीतर 36 से 51 अनुच्छेद निहित हैं जो सामाजिक सुशासन के ही पर्याय हैं। इसी के अंदर समान कार्य के लिए समान वेतन सहित कई समतामूलक बिंदुओं का प्रकटीकरण और आर्थिक लोकतंत्र का ताना-बाना दिखता है। डॉ. भीमराव आंबेडकर ने कहा था कि अगर आप मुझ से जानना चाहते हैं कि आदर्श समाज कैसा होगा, तो मेरा आदर्श समाज ऐसा समाज होगा जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर आधारित होगा। बारीक पड़ताल की जाए तो पता चला है कि आंबेडकर के इस कथन में सबके लिए समान अवसर का पूरा परिप्रेक्ष्य निहित है। एक और विचार यदि प्रशासनिक चिंतक फीडलैंडर का भी देखें तो स्पष्ट होता है कि सामाजिक सेवाएं किसी जाति, धर्म और वर्ग के भेदभाव के बिना किसी तक उपलब्ध होनी चाहिए। भारत एक संघीय राज्य है जिसकी प्रकृति पुलिस राज्य के विपरीत जन कल्याणकारी राज्य की है। यहां राज्यों का कर्तव्य है कि वे सुशासन विधि का निर्माण कर उक्त सिद्धांतों का अनुसरण करें। इसी को ध्यान में रखते हुए 14 जून 1964 को सामाजिक सुरक्षा विभाग की स्थापना की गई थी। 1972 में इस विभाग को शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय को सौंप दिया गया। फिर इसे स्वतंत्र मंत्रालय का दर्जा 24 अगस्त 1979 को समाज कल्याण मंत्रालय के रूप में दिया गया। मगर इस बार फिर इसकी प्रकृति से प्रभावित होते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1983-84 में इसका नाम बदलकर समाज एवं महिला कल्याण मंत्रालय कर दिया था। इसकी गौरव गाथा यहीं तक सीमित नहीं है। 1988 से इसे 'सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय' के नाम से जाना जाता है।

महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता लाने और महिलाओं के साथ हिंसा समाप्त कराने के विषय में देश ने एक लंबा रास्ता तय किया है जो महिलाएं रोज़मर्रा की ज़िन्दगी में कई किरदार निभाती हैं, उन्हें पुरुषों के समान स्थान देने में कई नीतियां धरातल पर उतारी गई। संविधान में सभी को समान मौलिक अधिकार देते हुए स्थानीय स्वशासन में तैंतीस फीसद की भागीदारी दी गई जो अब पचास प्रतिशत है। कई क़ानूनों के माध्यम से महिला सुरक्षा की चिंता की गई, मसलन 2005 में बनाया गया घरेलू हिंसा क़ानून। भेदभाव की परिपाटी को जड़ से ख़त्म करने के लिए सामाजिक सुशासन की धारा समय के साथ मुखर होती रही और उसी का एक और नारा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान है।

संविधान समावेशी और सतत् विकास की अवधारणा से युक्त है। कानून के समक्ष समता की बात हो, स्वतंत्रता व धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा हो या सबको समान अवसर देने की बात हो, उक्त संदर्भ संविधान में बारीकी से निहित हैं। इसमें सीमांत और वंचित वर्गों का कल्याण अवसर की समानता का बोध है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के अलावा वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल, महिलाओं की सुरक्षा साथ ही समाज के सभी वर्गों के लिए स्वतंत्र जीवन का अवसर उपलब्ध कराने की इसमें पूरी पटकथा है। इन सबके बावजूद भारत से भुखमरी का नामोनिशान मिटाने के लिए अभी बहुत लम्बा रास्ता तय करना बाकी है। जिस समावेशी विकास की बात होती रही है उसे तीन दशक का समय बीत चुका है। इतने समय में देश की आर्थिक व्यवस्था में आमूल-चूल बदलाव आ चुका है, मगर ग़रीबी, भुखमरी और अशिक्षा से निजात नहीं मिल पाई है। देश में हर चौथा व्यक्ति अशिक्षित और इतने ही गरीबी रेखा के नीचे हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक की ताज़ा रिपोर्ट नेपाल व अन्य पड़ोसी देशों से भी ख़राब हैं यहां बुनियादी समस्याओं की कसौटी पर समान अवसर की अवधारणा तो जैसे हांफ रही है। ज़ाहिर है, नीतिगत दायरा और बढ़ाना होगा। भारत सरकार 2030 के सतत् विकास लक्ष्य को हासिल करने के लिए दृढ़ दिखाई देती है, मगर मौजूदा स्थिति में जो पोषण की स्थिति है, उससे निपटने के लिए सुशासन पर अधिक ध्यान देने की क़वायद रहनी चाहिए।

भागीदारी की महत्ता एवं प्रासंगिकता के गुण सदियों से गाये जाते रहे हैं। हाल के सालों में सहभागिता व ग्रामीण विकास ने शासन के प्रमुख विषय के रूप में अपनी अलग व विशिष्ट पहचान बनाई है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक परिषद ने सरकार व प्रशासन के सभी स्तरों पर आम लोगों की सार्थक व व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने पर बल दिया हैं यह तभी संभव हो सकता है जब सभी के लिए सब प्रकार के अवसर उपलब्ध होंगे। लोकतंत्र के भीतर लोक और तंत्र तब अधिक परिणामदायक साबित होते हैं जब आम लोगों की शासन के कामकाज में दख़ल होती है। इसी संदर्भ को देखते हुए वर्ष 2005 में सूचना के अधिकार को भी लाया गया, जिसका शाब्दिक अर्थ सरकार के कार्यों में झांकना हैं जहां सत्ता जवाबदेह, पारदर्शी और संवेदनशीलता से ओत प्रोत हो, वहीं सुशासन निवास करता है। नीतियां जितनी अवसरों से युक्त होंगी, समता और सभी का समान विकास उसी पैमाने पर होगा। बीता एक वर्ष भारत और विश्व के लिए एक अभूतपूर्व संकट का दौर रहा है और कमोबेश यह स्थिति अभी भी है। कोविड-19 ने भी यह पाठ पढ़ाया है कि सबके लिए समान अवसर अभी बाकी हैं। लोगों के लिए सुविधाओं और अवसरों की कमी उन्हें अपनी पूरी क्षमता और दक्षता के विकास के उद्देश्य को हासिल करने से रोकती है। जहां रुकावट है वहीं अवसर का अभाव और सुशासन का प्रभाव धूमिल है। ''सबका साथ, सबका विकास'' नारे की प्रासंगिकता आज के दौर में कहीं अधिक हैं ज़ाहिर है समान अवसर सबको न केवल ताक़त देता है बल्कि सुशासन की राह को भी आसान बनाता है।

हाल के सालों में सहभागिता व ग्रामीण विकास ने शासन के प्रमुख विषय के रूप में अपनी अलग व विशिष्ट पहचान बनाई है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक परिषद ने सरकार व प्रशासन के सभी स्तरों पर आम लोगों की सार्थक व व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने पर बल दिया हैं यह तभी संभव हो सकता है जब सभी के लिए सब प्रकार के अवसर उपलब्ध होंगे। लोकतंत्र के भीतर लोक और तंत्र तब अधिक परिणामदायक साबित होते हैं जब आम लोगों की शासन के कामकाज में दख़ल होती है। इसी संदर्भ को देखते हुए वर्ष 2005 में सूचना के अधिकार को भी लाया गया, जिसका शाब्दिक अर्थ सरकार के कार्यों में झांकना हैं जहां सत्ता जवाबदेह, पारदर्शी और संवेदनशीलता से ओत प्रोत हो, वहीं सुशासन निवास करता है।

जर्मनी के नतीजों का संदेश

संजीव पांडेय

जर्मनी में संघीय चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। विश्व की एक शक्तिशाली महिला नेता एंजेला मर्केल की पार्टी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन ऑफ जर्मनी अपने मुख्य विरोधी द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से पिछड़ गई है हालांकि चुनाव नतीजे संकेत तो यही दे रहे हैं कि जर्मनी में अगली सरकारी में गठन में दोनों प्रमुख दलों को तीसरे और चौथे स्थान पर रही ग्रीन पार्टी और फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी का सहयोग लेना पड़ेगा। नई सरकार के गठन में अभी समय लग सकता है। ऐसे में जर्मनी को नया चांसलर क्रिसमस के आसपास ही मिल पाएगा। क्रिश्चियन यूनियन के आर्मिन लाशेट और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के ओलाफ स्कोल्ज चांसलर पद पर दावेदारी कर रहे हैं लेकिन सत्ता के चाअर लतग्न सेसद तके एक सौ अठारह सीटें पाने वाली ग्रीन पार्टी और बानवें सीटें पाने वाली फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी के हाथों में ही है। ग्रीन पार्टी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी 1998 से 2005 तक गठबंधन में रह चुकी हैं। वैसे में क बार इनका गठबंधन हो सकता है हालांकि दोनों दलों के बीच जलवायु परिवर्तन और आर्थिक मुद्दों सहित कई मसलों पर वैचारिक मतभेद क़ायद हैं, इसलिए इन्हें गठबंधन में लाने में थोड़ी मुश्किल आ सकती है। फिलहाल स्थिति यह है कि यदि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी भी सरकार बनाने की कोशिशों में जुटी है। वही मार्केल की पार्टी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन भी आसानी से हार नहीं मानने वाली, क्योंकि मतों के प्रतिशत के हिसाब से दोनों ही दर करीब हैं। सोशल डेमोक्रेट को पच्चीस प्रतिशत के करीब मत रहे, तो क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन को चौबीस प्रतिशत। सोशल डेमोक्रेटिक को दो सौ छह सीटें मिली हैं, तो क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन को एक सौ छियानवे। इसलिए सरकार के गठन में ग्रीन पार्टी और फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। ग्रीन पार्टी को पन्द्रह प्रतिशत वोट और एक सौ अठारह सीटें मिली हैं जबकि फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी को ग्यारह प्रतिशत वोट और बानवें सीटें मिली हैं।

जर्मनी के संघीय चुनाव में धुर वामपंथी और धुर दक्षिणपंथी दलों को जनता ने नकार दिया हे। यह चुनाव संकेत दे रहा है कि भविष्य में यूरोप अति दक्षिणपंथ और अति वामपंथ को स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन समाजवादी लोकतंत्र उसे पसंद होगा। हालांकि यूरोप को चीन और रूस मॉडल वाला वामपंथ पसंद नहीं है, लेकिन वह लोकतांत्रिक समाजवाद का पक्षधर है। दिलचस्प बात यह है कि सोशल डेमोक्रेट वामपंथी विचारों से प्रभावित हैं और कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को मानते हैं। जर्मनी के लोकतंत्र में समाजवादी लोकतांत्रिक समूह लंबे समय से मज़बूत स्थिति में रहे हैं। हिटलर से पहले भी जर्मनी में सोशल डेमोक्रेट प्रभावी थे।

जर्मनी में पिछले चार चुनावों में क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन सबसे बड़ी पार्टी बन कर उभरी थी। इस पार्टी ने वहां महागठबंधन बना कर शासन किया। क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन की नेता और जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल एक मजबूत वैश्विक नेता के रूप में उभरीं। उनकी ख़ूबी यह रही कि कुछ मुद्दों पर अमेरिका जैसे देशों से भी टकराव लेने में भी ज़रा भी हिचकीं नहीं। जर्मनी को अमेरिकी प्रभाव से निकालकर जर्मन हितों को सर्वोपरि रखा। जर्मनी विदेश नीति अमेरिकी दबाव में नहीं आई। रूस कोई देश को लेकर भी जर्मनी स्वतंत्र फैसला लेता रहा। इसलिए अमेरिकी प्रशासन के सामने अब बड़ी समस्या यही आएगी कि अगर जर्मनी में सोशल डेमोक्रेट सरकार बनाएंगे तो वे भी अमेरिकी दबाव में नहीं आएंगे।

मर्केल के कार्यकाल का जायज़ा लें तो साफ नज़र आता है कि सारे दलों ने मिलकर जर्मनी को मज़बूत करने का काम किया। जर्मनी की अर्थ व्यवस्था ने मर्केल के कार्यकाल में ब्रिटेन, फ्रांस और इटली से बेहतर प्रदर्शन किया। जर्मनी का निर्यात सिर्फ चीन और अमेरिका से पीछे रहा। मर्केल के कार्यकाल में बेरोज़गारी पर काबू पाया गया और पचास लाख अतिरिक्त रोज़गार उपलब्ध करवाया गया। दरअसल, पिछले कुछ सालों में मर्केल की विदेश नीति ने जर्मनी को अमेरिकी प्रभाव से मुक्त रखने में कामयाब रही है। अगर जर्मनी में सोशल डेमोक्रेट सरकार बनाते हैं तो जर्मन विदेश नीति पूरी तरह से अमेरिकी प्रभाव से मुक्त होगी। यूरोपीय संघ की राजनीति पर भी इसका असर पड़ना तय है। वैसे भी यूरोप में सोशल डेमोक्रेट का प्रभाव बढ़ रहा है। इसने दुनियाभर में दक्षिणपंथियों की चिंता बढ़ा दी है। यूरोप में भी सक्रिय दक्षिणपंथी सोशल डेमोक्रेट के बढ़ते प्रभाव से चिंतित हैं। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेट की सरकार अगर बनेगी, तो दक्षिणपंथियों की चिंता भी बढ़ेगी। फिर, मर्केल ने अमेरिका की इच्छा के ख़िलाफ़ जाकर रूस और जर्मनी के बीच गैस पाइपलाइन नार्ड स्ट्रीम-2 का निर्माण कार्य पूरा करवाया। अमेरिका ने इस गैस पाइप लाइन का जोरदार विरोध किया लेकिन जर्मनी अमेरिकी दबाव में नहीं आया। रूस के साथ जर्मनी ने अपने हितों को देखते हुए अपनी कूटनीति तय की थी। नार्ड स्ट्रीम-2 को अमेरिका ने रूसी विस्तारवाद बताया था। जबकि जर्मनी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि यह विशुद्ध रूप से व्यावसायिक योजना है। बाल्टिक सागर के रास्ते रूस से जर्मनी तक पहुंचने वाली यह पाइप लाइन यूरोप को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करेगी। नार्ड स्ट्रीम-2 गैस पाइप लाइन उन एशियाई देशों के लिए सीख है जो आपस में भाईचारा बनाने और आपसी सहयोग बनाने में विफल रहे हैं। ये देश पिछले चालीस सालों में एक गैस पाइप लाइन तक नहीं बना पाए। इसका उदाहरण प्रस्तावित ईरान-पाकिस्तान भारत गैस पाइप लाइन और तुर्कमेनिस्तान-अफग़ानिस्तान पाकिस्तान भारत गैस पाइप लाइन है जो कभी अमेरिकी दबाव में तो कभी आपसी तनाव के कारण अधर में लटकती रह गई।

जर्मनी की अर्थ व्यवस्था ने मर्केल के कार्यकाल में ब्रिटेन, फ्रांस और इटली से बेहतर प्रदर्शन किया। जर्मनी का निर्यात सिर्फ चीन और अमेरिका से पीछे रहा। मर्केल के कार्यकाल में बेरोज़गारी पर काबू पाया गया और पचास लाख अतिरिक्त रोज़गार उपलब्ध करवाया गया। दरअसल, पिछले कुछ सालों में मर्केल की विदेश नीति ने जर्मनी को अमेरिकी प्रभाव से मुक्त रखने में कामयाब रही है।

मर्केल के कार्यकाल में जर्मनी वैश्विक पटल पर काफी मज़बूत होकर उभरा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आने वाले समय में यह देश वैश्विक राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेट और ग्रीन पार्टी का मज़बूत होना दुनिया के लिए बड़ा संदेश है। इससे यूरोप की राजनीति भी अछूती नहीं रहने वाली क्योंकि यूरोपीय संघ में भी सोशल डेमोक्रेट से वैचारिक साम्यता रखने वाले समूह और पार्टियां अच्छी स्थिति में है। इस समय विश्व में दक्षिणपंथ उभार पर हैं। मानवाधिकारों का उल्लंघन एक गंभीर समस्या के रूप में सामने आया है। फिर, वैश्विक पटल पर लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षरण भी गंभीर प्रश्न खड़े कर रहा है। कारपोरेट प्रभावित लोकतंत्र ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। इसके साथ ही सीरिया और अफग़ानिस्तान सहित कई देशों में हिंसा और गृहयुद्ध के हालात विश्व में शरणार्थियों की समस्या भी बढ़ाई है। शरणार्थियों को लेकर मर्केल ने हमेशा उदारवादी नीति अपनाई। हालांकि यूरोप में सक्रिय दक्षिणपंथी गुट इसका जोरदार विरोध करते रहे। लेकिन जर्मनी ने मानवीय आधार पर सबके लिए दरवाज़े खुले रखे। ऐसे में जर्मनी में सोशल डेमोक्रेट भी सत्ता में आते हैं तो भी शरणार्थियों के प्रति मर्केल की तरह ही उदारवादी रवैया अपनाएंगे।

जर्मनी में सोशल डेमोक्रेट का मज़बूत होना यह भी संकेत देता है कि बेरोज़गारी जैसे मुद्दों पर यूरोप में संवेदनशीलता बढ़ रही है। हालांकि मर्केल ने बेरोज़गारी से निपटने की दिशा में अच्छा काम किया। लेकिन बावजूद इसके बेरोज़गार युवाओं की पसंद सोशल डेमोक्रेट रहे हैं। वहीं जलवायु परिवर्तन जैसा मुद्दा भी जर्मनी में छाया रहा। हाल ही में जर्मनी में बाढ़ आई थी। ग्रीन पार्टी को पंद्रह प्रतिशत वोट मिलना संकेत देता है कि जर्मन नागरिक जलवायु परिवर्तन को भी गंभीरता से ले रहे हैं। यूरोप की प्रमुख अर्थव्यवस्था जर्मनी में सोशल डेमोक्रेट का मज़बूत होना उन दक्षिण एशियाई देशों के लिए आंख खोलने वाला है, जहां कट्टरपंथी विचारधारा और घोर पूंजीवादी व्यवस्था मज़बूत हो रही है।❑❑

ख़ास ख़बरें

पड़ोसियों को डरा रहा चीन : पेंटागन

वाशिंगटन: पेंटागन ने कहा कि चीन अपने पड़ोसियों को डरा रहा है और उनसे जबरन ऐसा व्यवहार कराने की कोशिश कर रहा है, जो उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा या आर्थिक हितों के अधिक अनुरूप है। पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन किर्बी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि चीन अपने पड़ोसियों को लगातार डरा रहा है और उनसे जबरन ऐसा व्यवहार कराने की कोशिश कर रहा है, जो चीन के राष्ट्रीय हितों या उसके आर्थिक हितों के अधिक अनुरूप हैं। हमें नहीं लगता कि यह एक खुले एवं स्वतंत्र हिंद-प्रशांत के अनुकूल हैं।

स्कूलों में मास्क से छूट देने पर विचार

मियामी : अमरीका में कोविड-19 के मामलों में कमी आने पर कुछ स्कूल अपने यहां मास्क संबंधी नियमों में छूट देने पर विचार कर रहे हैं लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर पिछले कुछ सप्ताह में बढ़ते मौत के मामले, कुछ ग्रामीण अस्पतालों के दबाव में होने के संकेत और करीब आती ठंड ने उन्हें दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया है। अमेरिका में हर दिन औसतन 73.000 मामले आ रहे हैं जो 13 सितंबर को आए 1,73,000 मामलों से कम हैं और अस्पताल में भर्ती कोविड-19 मरीज़ों की संख्या सितंबर के बाद से आधी रह गयी है।

कर्नाटक में भी कोरोना का नया वेरिएंट

बेंगलुरु : कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के॰ सुधाकर ने कहा कि कोरोना वायरस के एवाई. 4.2 प्रकार के दो संदिग्ध मामलों की पहचान की गई है और नमूनों को जीनोम अनुक्रमण के लिए एक प्रयोगशाला में भेजा गया है। सुधाकर ने बताया कि वायरस के एवाई 4.2 प्रकार दो संदिग्ध मामले हैं और मैंने अपने विभाग को इसकी पुष्टि के लिए जीनोमिक अनुक्रमण के लिए नमूने भेजने का निर्देश दिया है।

आम नागरिक से शादी की जापान की राजकुमारी माको ने

टोक्यो : जापान की राजकुमारी माको ने शाही दर्जे को ठुकराते हुए अरबों की दौलत छोड़कर अपने प्रेम की ख़ातिर एक आम नागरिक से ब्याह रचा लिया है। चार वर्ष पहले कॉलेज के दिनों में प्रेमी केई कोमुरो से सगाई का ऐलान करने के बाद माको को इतनी आलोचना झेलनी पड़ कि उन्हें पोस्ट ट्रॉमैटिक स्ट्रैस डिसआर्डर तक हो गया, लेकिन उन्होंने अंतत: कोमुरो से शादी की और शाही परिवार छोड़ दियां। बीते 30 वर्ष की हुई माको ने अपने 30 वर्षीय प्रेमी केई कोमुरो की खाति शाही परिवार से मिलने वाले 13 लाख डॉलर भी ठुकरा दिए जो आमतौर पर शाही दर्जा दोड़ने पर आम जापानी नागरिक बनने पर राजकुमारियों को दिए जाते हैं।

इर्शादाते रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम

हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने इर्शाद फरमाया ''तीन बातें अगर किसी शख़्स के अंदर पाई जाएं तो अल्लाह तआला उसको क़यामत के दिन अपनी हिफाज़त में ले लेगा और उसे जन्नत में दाख़िल करेगा।

(1) कमज़ोरों के साथ नर्मी का बर्ताव। (2) वालिदैन के साथ शफ़क़त व मुहब्बत और, (3) गुलामों (और ख़ादिमों) के साथ अच्छा सुलूक।

और तीन सिफ्तें ऐसी हैं कि वह जिस शख़्स में पाई जाएंगी अल्लाह उसको अपने अर्श के साया में जगह देगा, उस दिन जब उसके साया के सिवा और कोई साया न होगा :

(1) ऐसी हालत में वुज़ू करना जबकि वूज़ू करने को तबीयत न चाहे (मसलन सख़्त जाड़े के दिनों में) (2) तारीक रातों में मस्जिद में जाना (ताकि जमाअत में शरीक हो) और (3) भूखे आदमी को खाना खिलाना।'' (तरग़ीब व तरहीब)

हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं ने नबी सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम को कहते सुना, आप सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम कअब बिन अजरह से फरमा रहे थे :-''ऐ कअब बिन अजरह! नमाज़ अल्लाह से करीब करने वाली चीज़ है और रोज़ा जहन्नम से बचाने के लिए ढाल की हैसियत रखता है और सदक़ा गुनाहों को इस तरह खत्म कर देता है कि जैसे आग पानी को बुझा देती है।

ऐ कअ्ब बिन अजरह! लोग दो क़िस्म के हैं, एक वह शख़्स जो अपने आपको दुनिया के मताए हक़ीर के एवज़ बेच देता है तो वह शख़्स अपने को गिरफ्तारे बला करता है और दूसरा वह शख़्स जो अपने आपको खरीदता है और इस तरह जहन्नम से अपनी गर्दन को छुड़ाता है।'' (तरग़ीब व तरहीब)

तश्रीह : मतलब यह है कि दुनिया में दो तरह के लोग पाए जाते हैं एक 'बन्दए दुनिया' ऐसे लोग खुदा के अज़ाब में गिरफ्तार होंगे और दूसरे लोग वह हैं जिन्होंने अपने आपको हुब्बे दुनिया से बचाया और खुदा की बन्दगी में लगे रहे, ऐसे लोग क़यामत के दिन जहन्नम से नजात पाएंगे।

हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने उन लोगों से जो आप सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम के पास बैठे हुए थे फरमाया: ''तुम लोग मुझे छः चीजों की ज़मानत दो तो मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत दूंगा। लोगों ने पूछा कि वह छः बातें क्या हैं ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम! आप सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने फरमाया वह यह हैं : नमाज़ पढ़ना, ज़कात देना, अमानत में ख़यानत न करना, शर्मगाह, पेट और जबान की हिफाज़त व निगरानी करना। (तरग़ीब बहवाला तबरानी)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि॰ अन्हु नबी सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम से रिवायत करते हैं, आप सल्ल॰ ने फरमाया कि ''हमारा रब दो आदमियों के अमल से बहुत खुश होता है, एक वह जो (जाड़े के ज़माने में) अपने नर्म बिस्तर और लिहाफ़ से अलग होकर और अपनी बीवी और बच्चों से जुदा होकर रात के वक़्त नमाज़ को जाता है, हमारा रब अपने फरिश्तों से फरमाता है कि देखो मेरे इस बन्दे को! इसने अपना बिस्तर और लिहाफ़ छोड़ा और अपनी बीवी बच्चों से अलग होकर नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ा हो गया क्योंकि इसके अंदर ख़्वाहिश है उन नेमतों की जो मेरे पास हैं और उसे डर लगा हुआ है उस अज़ाब का जो मेरे यहां होगा।

और दूसरा वह शख़्स जिसने अल्लाह की राह में जिहाद किया, मुजाहिदीन की फौज ने शिकस्त खाई और भागी और यह शख़्स जानता है कि मैदाने जिहाद से भागने का क्या नतीजा होता है और मैदाने जंग में जमे रहने का क्या सिला मिलता है। यह सोचकर वह जंग करता रहा यहां तक कि वह शहीद हो गया। ऐसा उसने इसलिए किया कि वह मेरे इनामात की ख़्वाहिश रखता है और मेरे अज़ाब से डरता है, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल अपने मलाइका से फरमाता है, देखो मेरे इस बन्दे को! यह मैदाने जंग में दोबारा वापस हुआ इसलिए कि इसको मेरे इनाम की ख़्वाहिश है और इसे मेरे अज़ाब का डर है, देखो वह लड़ता रहा यहां तक कि लड़ते लड़ते जान दे दी।'' (मुस्नद अहमद) ❑❑

आए हैं जो रसूल का दरबार देखकर

फैज़े जमाले अहमदे मुख़्तार देखकर
खुश हूं जहां को मतलए अनवार देखकर
वस्सुब्ह कहिए ताबिशे रुख़सार देखकर
वल्लैल पढ़िए गेसूए ख़म्दार देखकर
इंसानियत के हुस्न का अंदाज़ा कीजिए
खुलुके अज़ीम सय्यदे अबरार देखकर
जी चाहता है चूम लूं उनकी नज़र को मैं
आए हैं जो रसूल का दरबार देखकर
ईमां हैं जिनका आपकी मुश्किल कुशाई पर
घबराएं क्यों वो राह को दुश्वार देखकर
रिज़वां तेरी बहिश्त भी गुलरंग है मगर
क्या देखें हम मदीने का गुलज़ार देखकर
पेशे नज़र है नक़्शे कफ़े पाए मुस्तफ़ा
चलता नहीं मैं वक़्त की रफ्तार देखकर
रहमत ने बढ़के मुझको गले से लगा लिया
उनकी नज़र को मेरी तरफ़दार देखकर
रूहूल अमीं न भी न जहां बार पा सके
आए वो बारगह मेरे सरकार देखकर
वो गुल कहां कि तेरा मुमासिल कहूं जिसे
बैठा हूं दो जहां के चमनज़ार देखकर
जिसको मिला हो रहमते कौनैन का लक़ब
बांटे वो क्यों अक़ारिबो अग़यार देखकर
अल्लाह रे ये आईनए सीरते रसूल
हर दीदावार है नक़्श ब-दीवार देखकर
कुदरत ने नेमतों का ख़ज़ाना लुटा दिया
इनामे कुल का उनको सज़ावार देखकर
ईसा ने खुद वुरूदे मुबारक की दी नवेद
दुनिया को आपके लिए बीमार देखकर
आई है जिनको नींद दयारे हबीब में
मरता हूं उनकी क़िस्मते बेदार देखकर
बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तूई कहके चुप हैं सब
ना ताक़तिए ताक़ते गुफ्तार देखकर
सौ बार देखने की तमन्ना हुई हफीज़
उनकी गली को आए जो इक बार देखकर

नूरे क़ुरआन

(सूरा अल बैयना नं॰ 98)

अनुवाद और व्याख्या : शैख़ुल हिन्द र.अ.

हालांकि उन लोगों को यही आदेश हुआ था कि अल्लाह की इस प्रकार बंदगी करें कि बंदगी को उसी के लिए शुद्ध रखे। इब्राहीम के तरीक़े पर।

अर्थात् हर प्रकार के पाप और झूठ से अलग होकर ख़ालिस अकेले अल्लाह की उपासना करें और इब्राहीम अलै. की भांति चारों ओर से हटकर उसी एक मालिक के गुलाम बन जायें और किसी प्रकार के किसी कार्य में एक अल्लाह के सिवा किसी को स्वेच्छाचारी न मानें।

और नमाज़ की पाबंदी रखें और ज़कात दिया करें और यही दृढ़ लोगों का रास्ता है।

अर्थात् ये चीज़ें प्रत्येक दीन में पसंद की गई है। उन्हीं का विस्तार यह रसूल करता है फिर अल्लाह जाने ऐसी पवित्र शिक्षा से क्यों बिदकते हैं।

जो लोग अहले किताब और मुश्रिकों में से सच्चे दीन के इंकारी हुए वे दोज़ख़ की आग में जायेंगे। सदैव उसमें रहेंगे।

अर्थात् ज्ञान का दावा रखने वाले अहले किताब हों या अज्ञानी मुश्रिक, सच्चाई का इंकार करने पर सबका प्रतिफल एक है वही दोज़ख़, जिससे कभी छुटकारा नहीं।

वे लोग पूरी सृष्टि से ख़राब हैं।

अर्थात् पशुओं से भी अधिक अपमानित और बुरे।

निःसंदेह जो लोग ईमान लाये और भले काम किए वे लोग पूरी सृष्टि से बहुत अच्छे हैं।

अर्थात् जो लोग सब रसूलों और किताबों पर ईमान लाये और भले कार्यों में लगे रहे, वही सृष्टि में सबसे अच्छे हैं। यहां तक कि उनमें के कुछ व्यक्ति, फरिश्तों से आगे निकल जाते हैं।

उनका बदला उनके पालनहार के यहां सदैव रहने के बाग़ हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। जहां वे सदैव रहेंगे। अल्लाह उनसे प्रसन्न रहेगा और वे अल्लाह से प्रसन्न रहेंगे।

अर्थात् जन्नत के बाग़ों और नहरों से बढ़कर अल्लाह की प्रसन्नता की दौलत है, बल्कि जन्नत की तमाम नेमतों की वास्तविक आत्मा यही है।

रुकू नं॰ 1

यह उस व्यक्ति के लिए है जो अपने रब से डरता है।

अर्थात् यह उच्च स्थान प्रत्येक को नहीं मिलता, केवल उन बंदों का हिस्सा है जो अपने रब की नाराज़ी से डरते हैं और उसकी अवज्ञा करने के पास भी नहीं जाते।

(सूरा अल ज़िलज़ाल नं॰ 99)

यह सूरा मदीना में उतरी इसमें 8 आयतें हैं।

प्रारंभ करता हूं मैं अल्लाह के नाम से जो असीम कृपालु महादयालु है।

जब ज़मीन को उसके भूचाल से हिला दिया जायेगा।

अर्थात् अल्लाह सारी ज़मीन को एक भयानक कंपन से हिला डालेगा। जिसके कंपन से कोई भवन और कोई पहाड़ या वृक्ष ज़मीन पर खड़ा नहीं रहेगा, सब ऊंचाई-नीचाई बराबर हो जायेगी, ताकि हश्र का मैदान बिल्कुल समतल और साफ हो जाये और यह मामला क़यामत में दूसरी बार सूरा फूंकने के समय होगा।

नअ्ते शरीफ

सूए तैबा जाने वालो! मुझे छोड़कर न जाना
मेरी आंखों को दिखा दो शाहे दीं का आस्ताना
हैं वो जालियां सुनहरी मेरी हसरतों का मेहवर
वो संभाला मुझको देंगे जो हैं ख़ास रब के दिलबर
मुझे पहुंच कर मदीने, नहीं लौट कर है आना
मैं तड़प रहा हूं तन्हा मेरी बेबसी तो देखो
मैं असीरे रंज व ग़म हूं मेरी बेकली तो देखो
ज़रा रौज़ए नबी का मुझे रास्ता दिखा दो
दरे मुस्तफ़ा पे मेरी जब हाज़िरी लगेगी
मुझे फिर करम से उनके नई ज़िन्दगी मिलेगी
मेरे लब पे रात दिन है शबे बतहा का तराना
कोई कल का एक पल का नहीं कुछ भी है भरोसा
मुझे हम सफ़र बना लो कहीं रह न जाऊं प्यासा
दरे मुस्तफ़ा है इश्रत मेरा आख़िरी ठिकाना

राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस की बदलती राजनीति

राकेश कपूर

पिछली 20वीं सदी का भारत का इतिहास कमोबेश देश को आज़ादी दिलाने वाली कांग्रेस पार्टी का इतिहास ही रहा है मगर इस वर्तमान 21वीं सदी में यह पार्टी विभिन्न टुकड़ों में बिखर चुकी है परंतु अब इस पार्टी में श्री राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जिस तरह नया जोश भरने की शुरुआत की है उससे पार्टी के बिखरे हुए समूहों में विश्वास पैदा हो रहा है कि कांग्रेस पुन: खड़ी हो सकती है। कांग्रेस से अलग हुए विभिन्न दल जैसे तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, वाईएसआर कांग्रेस आदि अपने-अपने राज्यों में बहुत मज़बूत माने जाते हैं विशेषकर पं॰ बंगाल में ममता बनर्जी भाजपा के ख़िलाफ़ सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरी हैं परंतु राष्ट्रीय स्तर पर उनकी स्वीकार्यता विशेषकर उत्तर भारत व दक्षिण के राज्यों में राहुल गांधी की अपेक्षा बहुत कम है। यही स्थिति राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता श्री शरद पवार की है, हालांकि उनकी पहचान उत्तर भारत के राज्यों में भी एक सुलझे हुए राजनीतिज्ञ की है परंतु राहुल गांधी की नेहरु-गांधी परिवार की विरासत के मद्देनज़र उनकी स्वीकार्यता भी एक मराठा नेता के रूप में ही है। पूरे भारत में नेहरू/गांधी परिवार का रुतबा अभी तक स्वतंत्र भारत को संवारने वाले नेतृत्व के रूप में माना जाता है जिसका प्रमाण लोकसभा में पहुंचे हैं। भारत के प्रत्येक गांव में आज भी नेहरू/गांधी परिवार की पहचान है और कांग्रेस के मुरीद भी हैं।

राहुल गांधी की यही सबसे बड़ी शक्ति है जिसके सहारे वह कांग्रेस की पुनर्संचरना देश के बदले हुए स्वरूप के अरूप करना चाहते हैं। हाल ही में कम्युनिस्ट नेता कन्हैया कुमार को कांग्रेस पार्टी में लेकर राहुल गांधी ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि पार्टी में जो जी-23 नेताओं का गुट है उसे समयानुरूप स्वयं को बदलने की ज़रूरत है जिससे देश के 65 प्रतिशत युवाओं की आकांक्षाओं पर कांग्रेस खरी उतर सके।

राहुल गांधी की योजना है कि कन्हैया कुमार को उत्तर प्रदेश के चुनावों में इस तरह उतारा जाये कि भाजपा द्वारा खड़ा किया गया राजनैतिक विमर्श कांग्रेस के आर्थिक व सामाजिक समन्वयता के विमर्श के सामने ढेर हो जाये। साथ ही राज्य की जातिमूलक पार्टियों जैसे समाजवादी पार्टी व बहुजन समाज पार्टी के जाति समूहों को गोलबंद करके खड़े किये गये राजनैतिक विमर्श को ग़रीबों के सकल हितों के विरुद्ध सिद्ध किया जाये परंतु उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जिस तरह किसानों को गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा के बेटे की गाड़ी के नीचे रौंदने की घटना घटी है उससे उत्तर प्रदेश की समस्त खेतिहर ग्रामीण जातियों के एकजुट हो जाने की संभावना बढ़ गई है। इसका लाभ उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय दल लेने की कोशिश करेंगे परंतु श्रीमति प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे पर जिस तरह दिलेरी का परिचय देते हुए भाजपा को सुरक्षात्मक पाले में खड़ा कर दिया था जबकि ज़मीन पर उसका सांगठनिक ढांचा मजबूत हो लेकिन भारत का चुनावी इतिहास यह भी है कि किसी पार्टी का तेज़ अभियान चलने पर संगठन खुद- ब-ख़ुद बनता चला जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 1989 के वे लोकसभा चुनाव हैं जब रातोंरात विश्वनाथ प्रताप सिंह का जनता दल खड़ा हो गया था और बोफोर्स के मुद्दे पर लोगों ने इस पार्टी को डेढ़ सौ के लगभग सीटें दे दी थीं।

इस हक़ीक़त को कांग्रेस का जी-23 समूह भी अच्छी तरह समझताा है जिसे देखते हुए वह राहुल गांधी के नेतृत्व के प्रति अपने तेवर ढीले करने की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। इसी दल के एक सदस्य कहे जाने वाले वरिष्ठ नेता श्री कपिल सिब्बल लखीमपुर खीरी मसले पर राहुल व प्रियंका की तरफदारी में टीवी चैनलों पर दिखाई दिये और उन्होंने साफ कहा कि प्रियंका की सीतापुर में की गई गिरफ्तारी पूरी तरह ग़ैर क़ानूनी और असंवैधानिक थी।

जी-23 के सभी नेताओं में उन्होंने यह हक़ीक़त सबसे पहले स्वीकार की कि कांग्रेस में अब पुरानी सोच के साथ राजनीति करने के दिन लद चुके हैं और लोगों का रुझान श्री राहुल गांधी के प्रति है। वैसे कांग्रेस का इतिहास बताता है कि बड़े नेताओं

बाक़ी पेज 11 पर

दिल्ली के दिल को बयां कर रहा है सेंट्रल पार्क दिल्ली का सेल्फी प्वाईंट

दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनाट प्लेस को कैमरे में क़ैद करने के लिए लोकेशन ढंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए सेंट्रल पार्क में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) ने अलग प्रयोग किया है। प्रयोग के तौर पर यहां पर एक सेल्फी प्वाईंट बनाया गया है। इसमें तीन दिल बनाए गए हैं, जिन्हें रंग दिया गया है। यह सेल्फी प्वाईंट यहां आने वाले पर्यटकों के लिए विशेषकर युवाओं के लिए सेल्फी का मुख्य आकर्षण केन्द्र बन गया है।

सेंट्रल पार्क में आने वाले लोग इन दिलों के साथ खूब सेल्फी ले रहे हैं। युवा लोग सेल्फी प्वाईंट ले रहे है। युवा लोग सेल्फी प्वाईंट देखकर काफी उत्साहित नज़र आए। घूमने आए लोग सेल्फी प्वाईंट को अपने फोन में क़ैद करते नज़र आ रहे हैं। एनडीएमसी के उद्यान विभाग के निदेशक एस. चिल्लैया ने कहा कि कोरोना काल में घरों में क़ैद हुए लोग अब घरों से बाहर घूमने निकल रहे हैं। लोग उन कठिन दिनों की याद भूलने की कोशिश में अपने पसंदीदा स्थलों का रुख़ कर रहे हैं। दिल्ली और देशभर से आने वाले लोगों के लिए कनॉट प्लेस भी ऐसे ही स्थलों में शुमार है। चूंकि कनाट प्लेस को दिल्ली का दिल भी कहा जाता है इसे देखते हुए यहां पर दिल की तीन आकृति बनाई है। उन्होंने कहा कि यह सेल्फी प्वाईंट लोगों को इतना पसंद आएगा, हमें भी इसकी उम्मीद नहीं थी। अब यहां आने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है। पार्क में लगे गगनचुंबी तिरंगे साथ-साथ लोग इस सेल्फी प्वाईंट पर भी फोटा खींच रहे हैं। चिल्लैया ने कहा कि पर्यटक अच्छी यादें लेकर जाए, इसके लिए ऐसे प्रयोग किए जा रहे हैं। ऐसे प्रयाग अन्य स्थलों पर भी किए जाएंगे।

उल्लेखनीय है कि कनाट प्लेस के इस सेंट्रल पार्क में देश का तिरंगा शान से लहरा रहा है। यह 60 फुट चौड़ा, 90 फुट लंबा और 07 फुट ऊंचे पोल पर लगा हुआ है, जो लोगों का भारतीय होने पर गर्व महसूस करवा रहा है। अब तिरंगा और सेल्फी प्वाईंट दोनों मिलकर लोगों को लुभा रहे हैं।

आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने तक देश के सौ शहरों में दौड़ेगी मेट्रो

केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा है कि अगले साल तक देश में 900 किलोमीटर क्षेत्र में मेट्रो का संचालन शुरू हो जाएगा। कोविड से पहले मेट्रो के यात्रियों की संख्या 85 लाख तक पहुंच गई थी। फिलहाल ये करीब 30-35 लाख है। कोविड के हालात सामान्य होते जी यह संख्या एक करोड़ हो जाएगी। केन्द्रीय सचिव ने कहा कि आज़ादी के सौ वर्ष पूरे होने पर कम से कम देश के सौ शहरों में मेट्रो चलेगी। अब देश में 500 किलोमीटर में मेट्रो चल रही है, तब 5000 किलोमीटर में चलाने का लक्ष्य है। पैसेंजर भी तब ढ़ाई करोड़ होंगे। मेट्रो की तुलना में मेट्रो लाइट, मेट्रो नियो और वाटर मेट्रो कम खर्चीले विकल्प हैं। मिश्र ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के तहत हमने बढ़ी छलांग लगाई है। ग्लोबल टेंडरों में देश की कंपनियां बाज़ी मार रही हैं। गर्व का विषय है कि अब भारत में तैयार कोच कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में चलेंगे।

यूपी मेट्रो रेल कारपोरेशन के एमडी कुमार केशव ने प्रदेश में चल रहे मेट्रो प्रोजेक्ट के अलावा प्रस्तावित प्रोजेक्टों के भी विस्तार की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लखनऊ में दूसरे चरण में मुंशी पुलिया से जानकीपुरम, आईआईएम लखनऊ से राजाजीपुरम, चारबाग़ से एसजीपीजीआई और इंदिरा नगर से अवध विहार योजन इकाना स्टेडियम तक करीब 47.94 किलोमीटर में मैट्रो चलाने की तैयारी है जबकि तीसरे फेज में अवध विहार योजना से एयरपोर्ट और सचिवालय से सीजी सिटी साउथ तक 32.03 किलोमीटर के दायरे में मैट्रो संचालन प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि कानपुर और आगरा में तेज़ी से मैट्रो का काम चल रहा है। कानपुर में नौ किलोमीटर के प्रायोरिटी कॉरिडोर जल्द शुभारंभ हो जाएगा।

दिल्ली में बन रहा फाइव स्टार सरकारी स्कूल

दिल्ली सरकार एक फाइव स्टार सरकारी स्कूल निर्माण करवा रही है। इसमें छत पर स्विमिंग पूल, बास्केटबॉल, टेनिस व वॉलीबोल कोर्ट और स्मार्ट क्लास जैसी सुविधाएं होंगी। करीब 39.73 करोड़ की लागत से बन रहा यह स्कूल एक वर्ष में तैयार हो जाएगा। दावा है कि यह देश का पहला अत्याधुनिक सरकारी स्कूल होगा, जिसमें सभी आलीशान सुविधाएं होंगी। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया ने हाल में मेहराम नगर में इस स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस का शिलान्यास किया। श्री सिसोदिया ने बताया कि स्कूलों को विश्वस्तरीय बनाने की दिशा में क़दम उठाते हुए दिल्ली सरकार ने भवन का डिजाइन बच्चों के संपर्ण विकास को ध्यान में रखकर तैयार कराया है। पढ़ाई के साथ-साथ खेलों का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा।

स्कूल में सेमी ओलंपिक साइज बेहतरीन स्विमिंग पूल बनाने का दावा किया गया है। इसके साथ ही डिजिटल लर्निंग के लिए उपयोगी 52 स्मार्ट क्लासरूम बनेंगे। सभी तकनीकों और संसाधनों से लैस 8 लैब बनाई जाएंगी। रेन-वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जैसी अत्याधुनिक सुविधा होगी। इतना ही नहीं, स्कूल में 800 लोगों की क्षमता वाले ऑडिटोरियम के साथ-साथ 1000 लोगों की बैठक क्षमता वाला ओपन एम्फी थिएटर भी बनेगा। दिल्ली सरकार की यह पहल सराहनीय है, जो आने वाले समय में दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में एक बढ़ा विकासात्मक क़दम साबित हो सकेगा।

महिलाओं का टैस्ट मैच चार दिन का ही रहना चाहिए

सबा करीम

पूर्व भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज़ सबा करीम का मानना है कि महिलाओं के टैस्ट मैच में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए और इसे चार दिन का ही रखा जाए। भारत और आस्ट्रेलिया के बीच गुलाबी गेंद के टेस्ट मैच में बारिश के कारण काफी समय ख़राब हुआ था। फिर पुरुषों की तरह महिलाओं के टैस्ट मैच को भी पांच दिन का करने की मांग उठी थी। पूर्व भारतीय विकेटकीपर सबा करीम ने इन तमाम मुद्दों पर बातचीत की, पेश है इस बातचीत के प्रमुख अंश :-

सवाल:- ऐसी मांग उठ रही है कि महिलाओं के टैस्ट मैच को चार की जगह पांच दिन का होना चाहिए?

जवाब:- मुझे लगता है कि यह चार दिन का ही होना चाहिए। बहुत लोग ये नहीं जानते हैं कि महिलाओं के टैस्ट मैच में प्रत्येक दिन आपको 100 ओवर डालने होते हैं यानि चार दिन में आपको 400 ओवर डालने होंगे। उसकी तुलना हम पुरुष क्रिकेट से करें तो सिर्फ एक दिन में 90 ओवर डालने होते हैं तो 450 ओवर आपको पांच दिन में डालने होते है। इसलिए मुझे लगता है कि नतीजा निकालने के लिए चार दिन ही काफी हैं। ये अलग बात है कि बारिश हो जाती है तो इसका असर पड़ जाता है लेकिन ये तो पुरुष क्रिकेट में भी होता है और कई मैच ड्रॉल भी होते हैं। पुरुष क्रिकेट में पिछले एक दशक में हम देखें तो हमें नतीजे देखने को मिले हैं। पुरुषों ने बहुत ज़्यादा आक्रामक क्रिकेट खेलना शुरू किया है और उसी तरह के परिवर्तन की ज़रूरत महिला क्रिकेट में भी है।

सवाल:- इंग्लैंड में बारिश बहुत होती है। 2019 विश्व कप में भी कई मैच बारिश के कारण धूले थे?

जवाब:- देखिए, देश के हिसाब से आप नियम नहीं बदल सकते हैं। वहां विश्व टैस्ट चैम्पियनशिप फाइनल था और इसी कारण एक दिन अतिरिक्त रखा गया था। तो मुझे नहीं लगता कि इस बारे में कुछ सोचा जा रहा है। बारिश तो कहीं भी हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि पुरुष या महिलाओं के टैस्ट मैच में एक अतिरिक्त दिन बढ़ाने की ज़रूरत है।

सवाल:- क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि किसी टेस्ट में निर्धारित संख्या में ओवर करवाए ही जाएं?

जवाब:- हम कड़ी पेनाल्टी के बारे में बात कर सकते हैं कि हर जितने ओवर डालने हैं, उतने ओवर डालें और अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर आपको इस प्रकार की पेनाल्टी होगी। वर्तमान में ऐसा करने पर कप्तान को एक मैच के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाता है। मुझे लगता है कि पेनाल्टी और ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि खिलाड़ियों को लगने लगे कि अगर हमने ओवर पूरे नहीं डाले तो उसका असर उसी मैच में होगा। इन सब बातों पर आइसीसी की तकनीकी समिति ध्यान दे तो उसका फायदा होगा।

सवाल:- आप क्रिकेटर ओर चयनकर्ता रहे हैं। आप बीसीसीआई के जीएम भी रहे। आपको क्या लगता है कि महिला क्रिकेट के लिए अभी ओर क्या होना चाहिए?

जवाब:- मैं भारत के नजरिये से कहूंगा कि अभी बहुत कुछ हो रहा है। हमारे घरेलू क्रिकेट में मैचों की संख्या बढ़ गई है और कई राज्य खेल रहे हैं। भारतीय महिला टीम ने टेस्ट क्रिकेट वापस खेलना शुरू कर दिया है। भारत में भी कम से कम तीन दिन के घरेलू मैच होने चाहिए। इस समय महिला क्रिकेट में वनडे या टी-20 की प्रतियोगिता होती है। अब ज़रूरी है कि इंटर स्टेट या मल्टी डे प्रारूप के सभी मैच आयोजित किए जाएं। इससे हमारी खिलाड़ियों को बहुत फायदा होगा।

बाक़ी पेज 11 पर

अगले वर्ष खेलूंगा या नहीं 'रिटेंशन' नीति पर निर्भर : धोनी

करिश्माई महेंद्र सिंह धोनी को इसमें कोई शक नहीं कि वह वर्ष 2022 में पीले रंग की जर्सी में दिखाई देंगे लेकिन इस समय वह नही जानते कि यह पीली जर्सी इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में उनकी फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स की होगी या नहीं। आइपीएल के अगले सत्र से 10 टीमों के होने का ज़िक्र करते हुए धोनी ने कहा कि देखिए, आप मुझे अगले वर्ष पीले रंग की जर्सी में देख सकते हैं। लेकिन मैं सीएसके के लिये खेलूंगा या नहीं? इस प्रश्न पर कई अनिश्चितितायें हैं जिसका बहुत सरल कारण है कि टूर्नामेंट में दो नई टीं आ रही हैं। उन्होंने कहा कि हमें -'रिटेंशन' (खिलाड़ियों को बरकरार रखने की) नीति के बारे में नहीं पता है। हम नहीं जानते कि कितने विदेशी खिलाड़ियों और भारतीय खिलाड़ियों को हम बरकरार रख सकते हैं और साथ प्रत्येक खिलाड़ी की धनराशि (मनी कैप) कितनी होगी इसलिए काफी अनिश्चितितायें हैं उन्होंने कहा कि जब तक नियम नहीं बनते, आप इस पर फैसला नहीं कर सकते। इसलिये हमें इसके लिये इंतज़ार करना होगा और उम्मीद करता हूं कि यह प्रत्येक के लिए अच्छा होगा। धोनी की इस प्रतिक्रिया से खलबली मच सकती है हालांकि अगर टीम के सूत्रों पर भरोसा किया जाये तो सीएसके अपने तीन खिलाड़ियों धोनी, ऑल राउंडर रविंद्र जडेजा और सलामी बल्लेबाज़ रूतुराज गायकवाड़ को बरकरार रखना चाहती है।

हृदय संबंधी समस्याओं के प्रति सजग रहें

पहले कोविड-19 के काल में हम अपने स्वास्थ्य संबंधित देखभाल को लेकर काफी सतर्क रह रहे हैं, यह एक महामारी है जिसका असर काफी समय तक रहता है, और इससे सावधानी बरतनी चाहिए और टीका आ जाने के बावजूद सतर्क रहने की आवश्यकता है। यों तो कुछ बीमारियों को उम्र के साथ जोड़ा जाता था, लेकिन अब बीमारियां जीवनशैली से जुड़ गई हैं, जैसे हृदय संबंधी समस्याएं। जिसे कुछ समय तक सिर्फ पुरुषों से जोड़कर देखा जाता है, अब महिलाएं भी इसकी चपेट में हैं। आंकड़ों की मानें तो पिछले कुछ सालों में महिलाओं के मामले पांच गुना बढ़ गए हैं। यूं तो महिलाओं होने वाली दिल की बीमारियों की फेहरिस्त काफी लंबी है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक महिलाएं हार्ट अटैक से जुड़ी बीमारियों से ज़्यादा ग्रसित होती हैं। इसकी एक ख़ास वजह भी है कि महिलाएं अक्सर अपने दिल में उठने वाले दर्द को नज़रअंदाज़ कर देती हैं।

इस बीमारी में धमनियां ब्लॉक हो जाती हैं और रक्त प्रवाह सही से नहीं हो पाता है। अधिकांशत: यह 65 वर्ष की आयु के लोगों की मौत का सबसे आम कारण हैं इस बीमारी के होने के प्रमुख कारण लॉ डेंसिटी लिपो प्रोटीन (एलडीएल) का अधिक होना है। यह कोलेस्ट्रॉल रक्तवाहिनी में पहुंचकर जम जाता है, जिस से दिल का दौरा पड़ सकता है। हाई डेंसिटी लिपो प्रोटीन (एचडीएल) कोलेस्ट्रॉल का कम होना, डायबिटीज, नियमित व्यायाम न करना एवं धूम्रपान करना, ये सब लक्षण दिल की बीमारियों को बढ़ाते हैं। मोटापा भी इस बीमारी का एक प्रमुख कारण है। अगर समय रहते दिल का ख़्याल रखें तो इस बीमारी से ख़ुद का बचाव कर सकती है।

जीवनशैली में करें ज़रूरी बदलाव

अध्ययनों से पता चलता है कि कम से कम 07 घंटे की अच्छी नींद दिल के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे धमनियां अच्छे से कार्य करती हैं। यदि आपके सोने में तकलीफ या आप पूरी रात सो नहीं पा रहे हैं, तो तुरंत डाक्टर से संपर्क करें। ब्लड प्रेशर का हाई होना कोरोनरी हार्ट अटैक पड़ने का सबसे बड़ा कारण है, जिसमें धमनियां ब्लॉक हो जाती हैं और रक्त प्रवाह सही से नहीं हो पाता। इसलिए महिलाओं को समय-समय पर अपना ब्लड प्रेशर अवश्य चेक कराना चाहिए। यदि ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, तो अपने खानपान पर विशेष ध्यान दें और नियमित तौर पर दवाई भी लें। हाई कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक होने का सबसे बड़ा कारण है, जो कि फैट से होता है। फैट भी अच्छा या बुरा दो तरह का होता है और सबसे बुरा फैट ट्रांस फैट को माना गया है, क्योंकि यह हार्ट के लिए काफी बुरा है। महिलाओं को अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल की जांच भी करवाते रहना चाहिए। साल दो साल में यह जांच ज़रूर ही करवाएँ। मधुमेह एक ऐसी बीमारी है, जो न सिर्फ केवल हार्ट के लिए ख़राब है, बल्कि यह किडनी को भी नुकसान पहुंचाती है। डायबिटीज से बचने के लिए अपने शुगर लेवल को नियंत्रित रखना चाहिए एवं व्यायाम करते रहना चाहिए।

सप्ताह में कम से कम पांच दिन 30 मिनट तक व्यायाम करना चाहिए, ताकि शरीर से हानिकारक तत्व बाहर निकल जाए और शरीर स्वस्थ रह सके। ऐसा माना जाता है कि जो लोग प्रतिदिन सुबह व्यायाम करते हैं, बीमारी उनसे दूर रहती है।

महिलाओं में यह देखने को मिलती है कि उनका वज़न अचानक बढ़ने लगता है तथा वह इस बात पर ग़ौर नहीं करतीं। जो ग़लत है। वज़न को कंट्रोल में रखें। यदि आप इस ख़तरे से बचना चाहते हैं, तो टहलने जाना चाहिए एवं पानी अधिक पीना चाहिए।

धूम्रपान नियमित तौर पर या कभी-कभी करना हमारे हृदय के लिए बहुत ख़राब है। तनाव से बचने के लिए नियमित तौर पर योग करना चाहिए और परिवार के साथ समय बिताना चाहिए। समय समय पर अपना पूर्ण चेकअप कराते रहनाा चाहिए, जिससे हृदय संबंधित समस्याओं के प्रति सजग रहे और उनका निवारण करने के प्रति जागरुक रहे।

शेष.... प्रथम पृष्ठ

जिनके पास अपने खास समर्थक हैं, टीएमसी त्रिपुरा के प्रद्योत देबबर्मा, राज्य के सबसे बड़े स्थानीय समूह टीआइपी आरए (द इंडिजीनस पीपुल्स रीजनल अलायंस) मोथा के मुखिया - जैसे नेताओं को भी शामिल करना चाह रही है। टीएमसी के एक नेता नाम न छापने की शर्त पर बताते हैं, ''ममता ऐसे लोगों को साध रही हैं, जो मुखर होंगे और जो संसद में असर छोड़ेंगे। इसके साथ ही वे टीएमसी की आवाज़ को पूरे राष्ट्र में पहुचाएंगे।''

ममता बनर्जी ने अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल के ज़रिए कांग्रेस के जी-23 नेताओं से बातचीत के दरवाज़े भी खुले रखे हैं, जो विभिन्न मामलों में वकील के रूप में राज्य और टीएमसी का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे पहले ही अन्य विपक्षी नेताओं से तारीफ बटोर चुकी हैं - मनीष तिवारी ने उन्हें झांसी की रानी, बताया तो गुलाम नबी आज़ाद ने उन्हें 'पूरब की शेरनी' कहा। सलमान खुर्शिद ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उनकी जीत को ''राहत और सुकून'' क़रार देते हुए कहा कि इससे ज़ाहिर हो गया है कि ''भाजपा को स्थायी चुनौती देने के लिए नए सिरे से योजना विकसित करने की आवश्यकता है।''

सियासी प्रेक्षकों का कहना है कि भाजपा को चुनौती देने के लिए ममता बनर्जी के साथ कांग्रेस से अलग हुए गुट के शामिल होने की प्रबल संभावना है। उन्हें विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करना चाहिए, यह सुझाव बढ़ता रहा है और टीएमसी अगले दो सालों में विधान सभा चुनावों में - उदाहरण के लिए, त्रिपुरा, गोवा या मेघालय में - सीटें जीतने में अगर सक्षम होती है तो ये आवाज़ें अधिक मुखर हो जाएंगी। ❑❑

शेष.... अब रविवार को भी ...

के लिए उपलब्ध होगी जिन्हें जांच की तत्काल ज़रूरत है। कार्यालय आदेश में कहा गया है कि यह रेखांकित किया जाता है कि ये सुविधाएं मौजूदा मानव संसाधन से ही शुरू की जाएगी। इसी तरह का आदेश राम मनोहर लोहिया अस्पताल और सफदरजंग अस्पताल के अधिकारियों ने भी जारी किया है। आरएमएल के जारी आदेश में कहा गया है कि यहां अन्य विभागों के अतिरिक्त नाक-कान गला रोग विभाग, नेत्र रोग विभाग व मूत्ररोग विभाग की भी ओपीडी खुलेगी। इसके अलावा दवा की दुकान भी खुलेंगी। डॉक्टर नौ बजे से दोपहर एक बजे तक मरीज़ों को देखेंगे। अस्पताल के जारी आदेश में कहा गया है कि इन ओपीडी में आने वाले मरीज़ों को भर्ती करने की ज़रूरत पर अन्य दिनों की ओपीडी से जोड़ा जाएगा।

फेडरेशन ऑफ रेजीडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (फोर्डा) के अध्यक्ष डॉ. मनीष कुमार ने कहा है कि इससे दबाव बढ़ेगा और चिकित्सकों के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा जिसका असर मरीज़ों पर भी होगा। डॉ. मनीष ने यह भी कहा है कि पहले ही कोरोना काल में डाक्टर ज़रूरत से अधिक काम कर रहे हैं। फोर्ड पदाधिकारी डॉ. कौशिक कुलसौरभ ने कहा कि यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय काम के घंटों का कोई भी अस्पताल बामुश्किल ही पालन करते हैं। ❑❑

शेष.... अगले दस सालों में ...

समक्ष कई तरह की चुनौतियां पेश की है, लेकिन भारत व सऊदी अरब के द्विपक्षीय रिश्तों को और प्रगाढ़ करने की हमारी कोशिशों पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। हमारे लिए भारत तीसरा सबसे बड़ा कारोबारी साझीदार है। वर्ष 2020-21 में सऊदी अरब से तीन अरब डॉलर का निवेश भारत में हुआ है। भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में सऊदी अरब से बड़े निवेश आ रहे हैं। हाल ही में सऊदी के एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड ने भारतीय कंपनी में 7.5 करोड़ डॉलर का निवेश किया है। भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिफाइनिंग और पेट्रो रसायन कारोबार में सऊदी अरामको 20 प्रतिशत इक्विटी ख़रीद रही है। रिलायंस के खुदरा कारोबार आरआरवीएल में सऊदी अरब के एक वेल्थ फंड ने 1.3 अरब डॉलर का भी टाटा समूह, विप्रो, टीसीएसी, टीसीआइएल, एलएंडटी की उपस्थिति पहले से मज़बूत हुई है। ❑❑

शेष.... महिलाओं का टैस्ट मैच...

इस समय अंडर-16 का कोई टूर्नामेंट नहीं होता है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द शुरू होना चाहिए।

सवालः- भारतीय महिला टीम के बारे में क्या कहेंगें.?

जवाबः- जेमिमा रोड्रिग्ज, रिचा घोषणा, पूजा वस्त्राकर जैसी युवा खिलाड़ी टीम में हैं। छोटे प्रारूपों में आपको युवा खिलाड़ियों की ज़रूरत होती है। आस्ट्रेलिया में हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा है। महिला खिलाड़ियों और क्रिकेट में विकास देखने को मिल रहा है।

सवालः- महिला बीबीएल की तरह क्या महिला आइपीएल जल्द शुरू किया जाएगा.?

जवाबः- मुझे लगता है कि आगामी दिनों में यह भी देखने को मिलेगा। महिला आईपीएल शुरू करने से पहले ज़रूरी है कि हम अपने घरेलू क्रिकेट को और मज़बूत बनाएं तभी हमारे पास कई खिलाड़ी निकलकर आएंगे। तभी हम कह सकते हैं कि हमारे पास इतने खिलाड़ी हैं कि छह या सात टीमों की महिला आइपीएल शुरू की जाए। ❑❑

ग़रीबी से निजात क्यों नहीं चाहतीं सरकारें?

पिछले पाँच-छः दशकों से देश के चुनावों में ग़रीबी सबसे प्रमुख मुद्दा रहा है। लेकिन तमाम राजनीतिक दलों की सरकारें इस मुद्दे पर गम्भीरता से काम करने से बचती रही हैं। सवाल यह है कि क्या सरकारें ग़रीबी ख़त्म करना ही नहीं चाहतीं? शायद! क्योंकि अगर ग़रीबी ख़त्म हुई, तो उनका यह प्रमुख चुनावी मुद्दा ख़त्म हो जाएगा। ज़ाहिर है भारत में ग़रीबी को चुनावी मुद्दा बनाकर तमाम सियासी दल वोट बटोरने का काम करते हैं और यही कारण है कि किसी भी दल सरकार यह नहीं चाहती कि देश ग़रीबी से ख़त्म हो। जबकि देश में आँकड़ों की बाज़ीगरी से काग़ज़ों में ग़रीबी कम हो रही है।

देश में तेज़ी से बढ़ती ग़रीबी के अनेक कारण हैं, जिनमें सबसे प्रमुख कारण बढ़ती जनसंख्या, भ्रष्टाचार, खेती सुधारों में शिथिलता, रूढ़िवादी सोच, भयंकर जातिवाद, चरम पर बेरोज़गारी, अशिक्षा, बीमारियाँ और हर लगभग 10 साल में महामारी का आना आदि शामिल हैं।

देश की जनसंख्या और महँगाई, दोनों में तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है, प्रति व्यक्ति आय में लगातार कमी आ रही है। इससे आय की असमानता बढ़ रही है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि जितनी सम्पत्ति देश के दो-तीन फ़ीसदी लोगों के पास है, उतनी ही सम्पत्ति बाक़ी 97-98 फ़ीसदी लोगों के पास है। एक अनुमान के मुताबिक, आज देश में क़रीब 20 फ़ीसदी लोगों के पास देश कि कुल 80 फ़ीसदी सम्पत्ति है। जबकि देश की 80 फ़ीसदी जनता के पास मात्र 20 फ़ीसदी ही है।

पिछले दो-तीन दशकों में देश में तेज़ी से हुए भ्रष्टाचार और करोड़ों-अरबों रुपये के घोटालों ने ग़रीबी को और अधिक बढ़ा दिया है। देश में बढ़ते पूँजीवाद के कारण नव उदारवादी और खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश की नीतियाँ ग़रीबों के लिए अहितकारी साबित हुई हैं। नेताओं और नौकरशाहों के तेज़ी से बढ़ते वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं के अलावा तथा उनके द्वारा एकत्रित अरबों की अवैध सम्पत्ति से अमीरी और ग़रीबी की खाई दिन-दिन बढ़ती जा रही है। क्या इसके लिए सरकार की आर्थिक नीतियाँ ज़िम्मेदार नही हैं?

सरकार अगर वाक़ई ग़रीबों के लिए कुछ करना चाहती है, तो सर्वप्रथम पर्याप्त भूमि, जल, शिक्षा, स्वास्थ्य, ईंधन और परिवहन सुविधाओं का विस्तार करे। प्रत्येक वर्ष इसकी समीक्षा और मूल्यांकन किया जाए, साधनों के निजी स्वामित्व, आय और साधनों के असमान वितरण एवं प्रयोग पर सख्त नियंत्रण की आवश्यकता है। ग़रीबी निवारण कार्यक्रमों का अधिकतम लाभ अमीरों के बजाय ग़रीबों को पहुँचाने का ठोस प्रयास होना चाहिए। इसके लिए ग़रीबों के कल्याण के लिए आर्थिक नीतियाँ बनाते हुए ग़रीबों को दो वर्गों में बाँटा जाए। एक वर्ग में वे ग़रीब हों, जिनके पास कोई कौशल है और वे स्वरोज़गार कर सकते हैं। दूसरे वर्ग में वे ग़रीब हों, जिनके पास कोई कौशल या प्रशिक्षण नहीं है और वे केवल मज़दूरी पर ही आश्रित हैं। प्रत्येक वर्ग की उन्नति के लिए अलग नीति बने। अमीरों और पूँजीवाद को बढ़ावा देने वाली नीतियों में बदलाव लाया जाए, साथ ही सरकार को संस्थानों को बड़े कारोबारियों को नहीं सौंपना चाहिए और न ही निजीकरण करना चाहिए। ताकि ग़रीबी और अमीरी के बीच की खाई को पाटा जा सके। देश को ग़रीबी के से छुटकारा मिल सके और महात्मा गाँधी के भारत नवनिर्माण का सपना साकार हो सके। आज देश में महामारी के मद्देनज़र किये गये लॉकडाउन से पैदा हुए हालात भी कहीं न कहीं ग़रीबी के लिए ज़िम्मेदार हैं। इन हालात से निपटने के उपाय सरकार नहीं कर रही है, जबकि उसके हाथ में है कि वह स्थिति में सुधार करे और बेरोज़गार हाथों को काम दे। सिर्फ़ सत्ता हथियाने के लिए बयानबाज़ी करने से देश नहीं चल सकता, उसके लिए उद्यम की ज़रूरत है, जिसकी इन दिनों काफ़ी कमी है। लेकिन ज़मीनी स्तर पर सरकार का लोगों से, उनकी समस्याओं और ग़रीबी से कोई सरोकार नज़र नहीं आता। अगर मज़दूरों की ज़रूरत पड़े और अपनी जाति में न मिले, तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के ऊपर अन्य पिछड़ा वर्ग को तरजीह दे दी जाती है।

शेष.... राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस ....

के एकतरफ जाने से लोगों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं होता। 1969 में जब श्रीमति इंदिरा गांधी ने कांग्रेस का पहली बार विभाजन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के मुद्दे पर किया था तो कांग्रेस के सभी बड़े नेता इंदिरा विरोधी गुट सिंडिकेट के साथ थे। यहां तक कि कांग्रेस शासित राज्यों के अधिसंख्य मुख्यमंत्री भी सिंडिकेट में ही थे। इसमें महाराष्ट्र के वी.पी. नाइक से लेकर राजस्थान के मोहन लाल सुखाड़िया और हिमाचल के वाई.एस. परमार तक शामिल थे। भारत का कोई ऐसा राज्य नहीं था जिसके कद्दावर कांग्रेस नेता इंदिरा के ख़िलाफ़ नहीं हों। इसमें बिहार के महामाया प्रसाद सिन्हा और पं. बंगाल के अतुल्य घोष तक शामिल थे। इसके बावजूद आम जनता इंदिरा गांधी के साथ खड़ी हो गई थी। इसकी वजह एक ही थी कि इंदिरा जी ने बदलते वक्त के अनुरूप कांग्रेस की राजनीति में परिवर्तन करने का संकल्प किया था। तब इंदिरा जी के साथ केवल बाबू जगजीवन राम और फख़रुद्दीन अली अहमद थे। इसके बाद 1977 में ही ऐसा हुआ जब कांग्रेस दूसरी बार विभाजित हुई है। उस समय स्व॰ प्रणव मुखर्जी इंदिरा गांधी जी के साथ जमकर डटे हुए थे। हालांकि फिलहाल कांग्रेस के विभाजन का कोई प्रश्न खड़ा नहीं हो रहा है बल्कि इसके पुनः एक जुट होने का प्रश्न चुनौती बनकर खड़ा हुआ है मगर पुराने इतिहास में एक समानता नेहरू/इंदिरा परिवार की विरासत है जो भारत में आज भी कांग्रेस की पहचान बनी हुई है। इसमें अंतर सिर्फ इतना आया है कि विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय दलों के प्रबल हो जाने से इंदिरा/नेहरू परिवार की प्रासंगिकता में कमी दर्ज हुई है लेकिन इसके बावजूद पूरे देश में 200 के लगभग लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा का सीधा मुक़ाबला कांग्रेस से ही है। इस तथ्य को देखते हुए कांग्रेस से अलग हुए कांग्रेस नामधारी दल ऐसी रणनीति बना सकते हैं जिससे वे समान विचारधारा वाले अन्य क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर एक महागठबंधन बना कर कांग्रेस के साये तले राष्ट्रीय चुनावों में उतर सकें। ज़ाहिर है ऐसे गठबंधन का नेतृत्व उन्हें राहुल गांधी के हाथ में देना ही उचित होगा। ❑❑

शेष.... मंज़र पस-मंज़र

यह है कि नोवाजा गजेटा के पत्रकारों को अलग अलग ढंग से उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। धमकियों और हिंसा का भी सामना करना पड़ा है। इस अख़बार ने सच्ची सूचना की राह में छह पत्रकार भी गंवाए हैं, जिसमें वह अन्ना पोलितकोवस्काजा भी शामिल हैं, जिन्होंने चेचन्या में युद्ध को अपनी लेखनी से बेपर्दा किया था। नोबेल समिति ने उचित ही रेखांकित किया है कि बहुत दबाव के बावजूद अख़बार के प्रधान संपादक मुराटोव ने अख़बार की स्वतंत्र नीति को छोड़ने से इंकार कर दिया है।

आज जब दुनिया में अधूरी सूचनाओं और फर्ज़ी ख़बरों की बाढ़ आज हुई है, तब पत्रकारिता के सच्चे टापुओं को पहचानना बहुत ज़रूरी है। अच्छी पत्रकारिता किसी भी शांति प्रयास से कम नहीं होती। आज जो लोग पत्रकारिता का उपयोग द्वेष और सांप्रदायिकता बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, उनके लिए तो इन नोबेल सम्मानों में विशेष संदेश छिपा है। अच्छी दुनिया के लिए ईमानदार पत्रकारिता चाहिए। आज अच्छी पत्रकारिता को रेखांकित और सम्मानित करना ज़रूरी है। नोबेल पुरस्कार से दुनिया में उन तमाम पत्रकारों को बल मिलेगा, जो सच्ची और न्यायपूर्ण पत्रकारिता को समर्पित हैं। समिति ने बिल्कुल सही कहा है कि स्वतंत्र और तथ्य आधारित पत्रकारिता सत्ता के दुरुपयोग, झूठ और युद्ध से बचाने का काम करती है। आज आम लोगों की भी यह ज़िम्मेदारी है कि सच्ची पत्रकारिता के पक्ष में खड़े हों।

SHANTI MISSION (HINDI WEEKLY) NEW DELHI Postal Registration No. DL(C)-01/1266/2021-23
Publishing Date : **24 Oct.2021** Posting Days : **MON. - TUE.** at **N.D.P.S.O.** New Delhi-110002 R.N.I. 57270/93

मंज़र पस-मंज़र — मीम.सीन.जीम

•संकट का सामना •सौ साल की मेहनत •पत्रकारिता का सम्मान

संकट का सामना

रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने इस बार भी नीतिगत दरों में बदलाव नहीं किया। यह लगातार आठवां मौक़ा है जब रेपो और रिवर्स रेपो दर को पूर्व स्तर पर रखा गया है। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि केन्द्रीय बैंक अभी दरों में उदार रुख़ बनाए रखने के पक्ष में हैं। नीतिगत दरें 2001 के बाद सबसे निचले स्तर पर बनी हुई है। अभी रेपो दर चार प्रतिशत और रिवर्स रेपो दर 3.35 प्रतिशत है हालांकि दरों को बहुत लंबे समय तक इतने न्यूनतम स्तर बनाए रखना भी संभव नहीं है। मौद्रिक नीति समिति ने यह संकेत भी दे दिया है कि आने वाले दिनों में वह उन प्रोत्साहन उपायों को वापस लेने का भी काम शुरू कर सकती है जो महामारी से अर्थ व्यवस्था को उबारने के लिए लिए किए गए थे। ज़ाहिर है, अगली बैठक में नीतिगत दरों में वृद्धि को लेकर कोई राय बने। फिलहाल रेपो और रिवर्स रेपो दर बदलाव नहीं करने का फैसला इसलिए भी लिया गया है ताकि बैंक कर्ज़ कम दरों पर मिलते रहें। त्यौहारी मौसम में लोग घर, गाड़ी और कई तरह का सामान खरीदते हैं और इससे बाज़ार में तेज़ी का रुख़ बनता है। अगर कर्ज़ सस्ते रहेंगे तो बाज़ार में मांग बनाने में मदद मिलेगी।

पिछले बीस महीनों में रिजर्व बैंक का जोर महामारी से ध्वस्त अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में रहा है। इसके लिए बैंक ने कई बड़े कदम उठाए, उद्योगों को राहत दी, बैंकों को नगदी मुहैया करवाई, खासतोर से छोटे और मझौले उद्योगों के लिए कर्ज़ सस्ता किया ताकि पूर्णबंदी के कारण बंद हो चुके उद्योग फिर से काम शुरू कर सकें। इसके साथ ही केन्द्रीय बैंक की चिंता महंगाई को लेकर भी कम नहीं दिखी।

पिछले बीस महीनों में रिजर्व बैंक का जोर महामारी से ध्वस्त अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में रहा है। इसके लिए बैंक ने कई बड़े कदम उठाए, उद्योगों को राहत दी, बैंकों को नगदी मुहैया करवाई, खासतोर से छोटे और मझौले उद्योगों के लिए कर्ज़ सस्ता किया ताकि पूर्णबंदी के कारण बंद हो चुके उद्योग फिर से काम शुरू कर सकें। इसके साथ ही केन्द्रीय बैंक की चिंता महंगाई को लेकर भी कम नहीं दिखी। महंगाई बेक़ाबू होने की वजह से भी नीतिगत दरों में वृद्धि करना संकट को और बढ़ाना ही होता है। हालांकि अर्थव्यवस्था में अब सुधार के संकेत दिखने लगे हैं लेकिन अभी भी सबसे बड़ा संकट मांग और उत्पादन का बना हुआ है। रिजर्व बैंक खुद मान रहा है कि उत्पादन अभी भी महामारी के पहले वाली स्थिति में नहीं आया है। इसके साथ बाज़ारों में मांग भी नहीं है। मांग और उत्पादन में सुस्ती छाई रहना चिंता पैदा करता है। अभी भी जो लोग खरीद कर रहे हैं, वे बहुत ज़रूरी होने पर ही पैसा निकाल रहे हैं। यानि लोगों के पास पैसे का संकट अभी भी है इसलिए रिजर्व बैंक के सामने बड़ी चुनौती मांग, उत्पादन और खपत के चक्र को फिर से चलाने की है।

महंगाई भी चिंता का कारण बनी हुई हैं रिजर्व बैंक का अनुमान है कि अगले वर्ष मार्च तक मुख्य मुद्रास्फीति 5.3 प्रतिशत रहेगी, जिसका पहले 5.7 प्रतिशत रहने का अनुमान था। यानि आने वाले समय में भी महंगाई से राहत मिलने के आसार नहीं लग रहे। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के लगातार बढ़ते दाम आग में घी का काम कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से हर चीज़ महंगी होती जा रही है। ऐसा नहीं कि पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों से रिजर्व बैंक परेशान नहीं है। वह खुद मान रहा है कि इन दोनों उत्पादों के दाम बढ़ने से जो महंगाई बढ़ रही है, उससे आमजन का जीना मुहाल हो गया है। इन दोनों उत्पादों पर शुल्कों में कटौती के लिए वह केन्द्र से कह भी चुका है लेकिन केन्द्र और राज्य इस मुद्दे पर जिस तरह की चुप्पी साधे हुए हैं, वह संकट को दिनोंदिन गंभीर ही बना रही है।

सौ साल की मेहनत

बीमारियों के ख़िलाफ़ चलने वाले मनुष्यता के सतत संघर्ष में एक अहम पड़ाव आया, जब डब्ल्यूएचओ ने मलेरिया के टीके आरटीएसएस को अपनी मान्यता दे दी। वैसे तो भांति-भांति के विषाणुओं और जीवाणुओं पर काम करने वाले कई टीके पहले से मौजूद हैं, लेकिन यह पहला मौक़ा है जब डब्ल्यूएचओ ने ह्यूमन पैरासाइट के ख़िलाफ़ किसी टीके के व्यापक उपयोग की सिफारिश की है। इसकी वैज्ञानिक अहमियत इस बात से समझी जा सकती है कि रिसर्चर्स पिछले सौ से इस बीमारी का प्रभावी टीका बनाने की कोशिश में लगे थे। मलेरिया से हमारा वास्ता लंबे समय से पड़ता रहा है और तमाम उपायों की बदौलत आज भले यह अपने खौफनाक रूप में नज़र न आता हो, लेकिन एक समय था, ख़ासकर 50 का दशक जब भारत में भी सालाना मलेरिया के सात करोड़ से ज़्यादा मामले सामने आते थे और आठ लाख तक मौतें दर्ज की जाती थीं। अब भारत में उतना बुरा हाल नहीं है लेकिन दुनियाभर में अब भी इससे हर वर्ष करीब चार लाख मौतें होती हैं। इसका सबसे ज़्यादा प्रभावी अफ्रीकी देशों में है। वहां पांच साल से कम आयु के बच्चे इसका सबसे ज़्यादा शिकार बनते हैं हालांकि इससे बचाव के उपाय भी कम नहीं किए जाते। 2019 में ही मलेरिया नियंत्रण और उन्मूलन पर तीन अरब डॉलर खर्च किए गए। मगर इसके बावजूद इन देशों में मलेरिया का आतंक कायम है। निश्चित रूप से इन इलाकों के लोगों के लिए यह टीका वरदान बनकर आया है। फिर भी सारी उम्मीदें इसी पर टिका देना समझदारी नहीं होगी। वैसे पायलट प्रोग्राम के दौरान इसके नतीजे उत्साहवर्धक रहे हैं, लेकिन फिर भी इसकी अपनी सीमाएं हैं। पहली बात तो यह समझने की है कि मलेरिया पैरासाइट के सौ से अधिक प्रकार हैं। आरटीएसएस टीका इनमें से एक प्लाज्मोडियम पाल्सिपैरम पर ही कारगर है, हालांकि यही सबसे ख़तरनाक माना जाता है और अफ्रीकी देशों में सबसे ज़्यादा प्रकोप भी इसी का होता है। दूसरी बात यह कि इस वैक्सीन के प्रभावी होने के लिए हर बच्चे को इसकी चार डोज देनी ज़रूरी होगी। पांच, छह और सात माह की आयु में तो चौथी डोज 18वें महीने में देने की ज़रूरत होगी। दूरदराज़ के इलाकों में बच्चों को समय से चारों डोज लगाना व्यवहार में आसान नहीं होगा। वैसे, अच्छी योजना बनाकर इस मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। मलेरिया की नई दवाओं को लेकर भी हाल कोई अच्छा नहीं रहा। इस तरह के आरोप लगे कि दवा कंपनियों को खासतौर पर ग़रीब मुल्कों की इस बीमारी में बड़ा मुनाफ़ा नहीं दिखा, इसलिए उन्होंने मलेरिया की नई दवाएं नहीं बनाईं। जिस तरह से बच्चों की ख़ातिर यह टीका आया है, कुछ वैसी ही पहल इस बीमारी की नई दवा बनाने को लेकर भी होनी चाहिए।

पत्रकारिता का सम्मान

शान्ति के लिए दो पत्रकारों को नोबेल सम्मान हासिल होना स्वागतयोग्य और अनुकरणीय है। आज दुनिया में जब अभिव्यक्ति पर संकट के बादल कुछ ज़्यादा मंडरा रहे हैं, तब पत्रकारों का सम्मान वास्तव में पत्रकारिता का सम्मान है। फिलीपींस की पत्रकार मारिया रसा और रूस के पत्रकार दिमित्री मुराटोव को 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार से नवाज़ा गया है। पत्रकारिता के लिए यह ऐसी सफलता है, जिससे मीडिया की समग्र गुणवत्ता पर सकारात्मक असर पड़ेगा। मारिया रसा और दिमित्री मुराटोव को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के उनके प्रयासों के लिए अगर सम्मानित किया जा रहा है, तो इससे दुनिया में लोकतंत्र और स्थायी शांति को ही बल मिलेगा।

मारिया रसा अपने मूल देश फिलीपींस में सत्ता के दुरुपयोग, हिंसा के इस्तेमाल और बढ़ती तानाशाही को उजागर करने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग करती रही है। उन्होंने वर्ष 2012 में खोजी पत्रकारिता के लिए एक डिजिटल मीडिया कंपनी की सह स्थापना की थी और अपने देश में विवादास्पद ड्रग के ख़िलाफ़ युद्ध पर ध्यान केन्द्रित किया, जिससे हज़ारों लोगों की जान बचाने में सफल हुई। फर्जी ख़बरों के ख़िलाफ़ रसा के समग्र काम पर भी दुनिया को ग़ौर करना चाहिए, उससे मीडिया की मज़बूती ही बढ़ेगी। दूसरी ओर रूसी पत्रकार दिमित्री आंद्रेयेविच मुराटोव ने नोवाजा गजेटा अखबार की सह-स्थापना की थी, जो नोबेल समिति के मुताबिक, आज उनके देश का सबसे स्वतंत्र समाचार पत्र हैं मुराटोव ने अपने देश में तेज़ी से बदलते प्रतिकूल हालात के बीच भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बचाव किया है। उनका रूसी अख़बार भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग, चुनावी धोखाधड़ी और ट्रोल अभियानों पर प्रश्न उठाते हुए कारगर पत्रकारिता को अंजाम देता रहा है। खास बात

आज जब दुनिया में अधूरी सूचनाओं और फर्ज़ी ख़बरों की बाढ़ आज हुई है, तब पत्रकारिता के सच्चे टापुओं को पहचानना बहुत ज़रूरी है। अच्छी पत्रकारिता किसी भी शांति प्रयास से कम नहीं होती। आज जो लोग पत्रकारिता का उपयोग द्वेष और सांप्रदायिकता बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, उनके लिए तो इन नोबेल सम्मानों में विशेष संदेश छिपा है। अच्छी दुनिया के लिए ईमानदार पत्रकारिता चाहिए।

बाक़ी पेज 11 पर

ज़रूरी ऐलान

आपकी ख़रीदारी अवधि पते की चिट पर अंकित है। अवधि की समाप्ति से पूर्व रक़म भेजने की कृपा करें।

रक़म भेजने के तरीक़े:-

❶ मनीआर्डर द्वारा ❷ Paytm या PhonePe द्वारा 9811198820 पर SHANTI MISSION

❸ ऑनलाइन हेतु बैंक खाते का विवरण
SBI A/c 10310541455
Branch: Indraprastha Estate
IFS Code: SBIN0001187

ख़रीदारी चन्दा

वार्षिक	Rs.130/-
6 महीने के लिए	Rs.70/-
एक प्रति	Rs.3/-

जानकारी के लिये सम्पर्क करें
साप्ताहिक
शांति मिशन
1, बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002
फोन : 011-23311455

अपने प्रिय अख़बार साप्ताहिक शांति मिशन को इंटरनेट पर देखने के लिये लॉगऑन करें:
www.aljamiat.in —— www.jahazimedia.com
Mob. 9811198820 — E-mail: Shantimissionweekly@gmail.com

जमीअत ट्रस्ट सोसायटी की तरफ से मुद्रक, प्रकाशक शकील अहमद सैयद ने शेरवानी आर्ट प्रिंटर्स, 1480, क़ासिमजान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली-6 से छपवाकर मदनी हाल, न. 1, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित किया। संपादक:- मोहम्मद सालिम, फोन:- 23311455, 23317729, फैक्स:- 23316173